राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, सोमवार , 03 दिसंबर 2025

वर्ष 14,अंक 230, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

नाटक कलाकारों में हुई जमकर मारपीट चले लाठी- डंडे शराब पीने के बाद हुआ विवाद..03

कर्नलगंज की सभी रेलवे क्रॉसिंगों पर लग रहा भीषण जामः प्रशासन मौन,जनता बेहाल..04

जल्लाद से कम नहीं ये जेलर! हाईकोर्ट के आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंका, मिलने गए सीएम को 8 बार लौटाया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पाकिस्तान की राजनीति में कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता. यहां प्रधानमंत्री जेल जाते हैं और जेलर 'किंगमेकर' की भूमिका में आ जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही जेलर की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसका रसूख शायद इस वक?त पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कम नहीं है. एक ऐसा सरकारी मुलाजि?म, जो वर्दी तो जेल पुलिस की पहनता है, लेकिन उसके तेवर किसी तानाशाह से कम नहीं हैं. हम बात कर रहे हैं रावलपिंडी की मशहूर अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट (जेलर) अब्दुल गफूर अंजुम की. वही जेल, जहां पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, 'कैदी नंबर 804' बनकर बंद हैं।

इस जेलर की कहानी पढ़कर आपको लगेगा कि क्या वाकई पाकिस्तान में कोई कानून-कायदा बचा है या फिर वहां 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' वाली कहावत ही संविधान बन चुकी है. अब्दुल गफूर अंजुम कोई आम जेलर नहीं हैं. वे पंजाब प्रेसिडेंट सर्विस के अफसर हैं और इन दिनों उनकी हनक ऐसी है कि वे हाईकोर्ट के जजों के आदेशों को भी सिगरेट के धुएं की तरह हवा में उड़ा देते हैं. जरा सोचिए, देश का एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है. उसका परिवार अदालतों के चक्कर काट रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने घर के मुखिया से मिलने दिया जाए. इस्लामाबाद हाईकोर्ट, जो देश की प्रतिष्ठित अदालतों में से एक है,

साफ-साफ आदेश जारी करती है. आदेश में कहा जाता है कि इमरान खान के परिवार को उनसे हफ्ते में कम से कम दो बार मिलने की इजाजत दी जाए. यह बुनियादी मानवाधिकार है. किसी भी कैदी को उसके परिवार और वकीलों से मिलने का हक होता है. लेकिन, जब यह आदेश लेकर इमरान का परिवार और वकील अडियाला जेल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो वहां उनकी मुलाकात होती है जेलर अब्दुल गफूर अंजुम के फरमान से. अंजुम साहब साफ कह देते हैं कि यह आदेश पूरा नहीं किया जा सकता. आप अंदाजा लगाइए, एक जेल सुपरिंटेंडेंट हाईकोर्ट के लिखित आदेश को मानने से इनकार कर रहा है. यह सिर्फ आदेश की अवहेलना नहीं है, यह न्यायपालिका के मुंह पर करारा तमाचा है. मानो जेलर साहब कह रहे हों कि जेल के अंदर मेरी अदालत चलती है, बाहर वालों की नहीं।

सीएम को एक नहीं, आठ बार बेइज्जत कर लौटाया

अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ इमरान खान के परिवार तक सीमित है, तो आप गलत हैं. इस जेलर का खौफ और रसूख इतना है कि वह एक चुने हुए मुख्यमंत्री को भी कुछ नहीं समझता. खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सुहेल आफरीदी, जी हां, एक सिटिंग सीएम अपने नेता इमरान खान से मिलने अडियाला जेल पहुंचे. एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे आठ बार. और आठों बार जेलर अब्दुल गफूर अंजुम ने उन्हें जेल के दरवाजे से ही वापस लौटा दिया. प्रोटोकॉल के हिसाब से एक मुख्यमंत्री का दर्जा बहुत बड़ा होता है. लेकिन अंजुम के सामने प्रोटोकॉल की कोई अहमियत नहीं है. सोचिए, जिस देश में एक जेलर एक मुख्यमंत्री को आठ बार मिलने से मना कर दे, वहां लोकतंत्र की क्या हालत होगी? यह घटना बताती है कि पाकिस्तान में असली ताकत चुनी हुई सरकारों के पास नहीं, बल्कि कहीं और है।

4 नवंबर से 'कालकोठरी' में तब्दील इमरान की सेल

जेलर अंजुम की मनमानी का सिलसिला यहीं नहीं रुकता. 4 नवंबर के बाद से तो उन्होंने अडियाला जेल में इमरान खान की सेल को एक तरह से 'ब्लैक होल' बना दिया है. तब से लेकर अब तक, इमरान खान को पूरी तरह अलग-थलग कर दिया गया है।

न तो उनके घर का कोई सदस्य उनसे मिल पाया है, न ही उनकी पार्टी का कोई करीबी नेता, और सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके वकीलों तक को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है. एक ऐसे शख्स को, जिस पर सैकड़ों मुकदमे लाद दिए गए हों, उसे अपने वकीलों से मिलने से रोकना, उसके कानूनी बचाव के अधिकार को छीनना है. यह सीधे तौर पर मानवाधिकारों का हनन है, लेकिन जेलर अंजुम को इसकी कोई परवाह नहीं है. ऐसा लगता है कि उनका मकसद सिर्फ इमरान खान को मानसिक रूप से तोड़ना है।

यह सिर्फ एक जेलर की कहानी नहीं है

अडियाला जेल के जेलर अब्दुल गफूर अंजुम की यह कहानी सिर्फ एक अफसर की मनमानी की दास्तां नहीं है. यह आज के पाकिस्तान का एक डरावना सच है. यह बताता है कि वहां वर्दी और बूटों की ताकत के आगे संविधान, कानून, अदालतें और चुनी हुई सरकारें कितनी बौनी हैं. जब एक जेलर हाईकोर्ट के आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक सकता है, तो समझिए कि उस देश में न्याय की उम्मीद करना रेगिस्तान में पानी तलाशने जैसा है. फिलहाल, 'कैदी नंबर 804' इस सिस्टम की चक्की में पीस रहा है और जेलर अंजुम उस चक्की को चलाने वाले एक क्रूर पहरेदार बने हुए हैं।

तो क्या हम रोहिंग्याओं के लिए रेड कार्पेट बिछा दें? आखिर क्यों आग बूबला हो सीजेआई सूर्यकांत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी 2 दिसंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में सुनवाई हुई. पांच रोहिंग्या शरणार्थियों की कथित कस्टोडियल डिसअपीयरेंस (हिरासत में गायब होने) की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने सख्त टिप्पणी की. उन्होंने कहा- 'जो अवैध रूप से देश में घुसते हैं, उनके लिए हम रेड कार्पेट तो नहीं बिछा सकते.' कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर तक टाल दी गई है, जब रोहिंग्या से जुड़े अन्य मामले भी सूचीबद्ध हैं।

सुप्रीम कोर्ट से 5 रोहिंग्या शरणार्थियों कस्टोडियल डिसअपीयरेंस पर केंद्र को नोटिस जारी करने की अपील की गई थी. हालांकि, सीजेआई की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजने से साफ इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान बेंच ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा, 'आप जानते हैं कि ये लोग घुसपैठिए हैं. हमारे नॉर्थ-ईस्ट का बॉर्डर बहुत संवेदनशील है।'

रेड कार्पेट बिछा दें?

उन्होंने आगे टिप्पणी करते हुए कहा, 'देश में क्या-क्या हो रहा है, आप जानते हैं? अगर कोई गैरकानूनी तरीके से आता है... तो क्या आप चाहते हैं कि हम उनके लिए रेड कार्पेट बिछाएं? वो सुरंगों से अंदर आते हैं और फिर आप कह रहे हैं कि उन्हें खाना, आश्रय, बच्चों के लिए शिक्षा... क्या हम कानून को इतना खींच दें? हैबियस कॉर्पस जैसी बातें बहुत कल्पनात्मक हैं।

रोहिंग्या भारत के नागरिक नहीं

सीजेआई ने आगे कहा, 'हेबियस कॉर्पस मांगना बहुत फैंसी बातें हैं. ये लोग अवैध प्रवासी हैं.' बेंच ने यह भी टिप्पणी की कि देश की सुरक्षा और सीमाओं की स्थिति को देखते हुए ऐसी याचिकाओं पर सहानुभूति दिखाना आसान नहीं है. याचिका में मांग की गई थी कि पांच रोहिंग्या शरणार्थियों को पुलिस हिरासत से 'गायब' कर दिया गया है और कोर्ट उनके ठिकाने का पता लगाने का आदेश दे. दरअसल, रोहिंग्या मुद्दा पिछले कई सालों से विवादास्पद रहा है. केंद्र सरकार बार-बार कहती आई है कि रोहिंग्या भारत के नागरिक नहीं हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं. 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार किया था. अभी देशभर में करीब 40,000 रोहिंग्या रह रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर बिना वैध दस्तावेज के हैं।

एक कहानी यह भी, स्ट्रक्रने लौटाई बूढ़े मां-बाप की खुशियां, घर से गायब हुई बेटी 13 साल बाद लौटी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

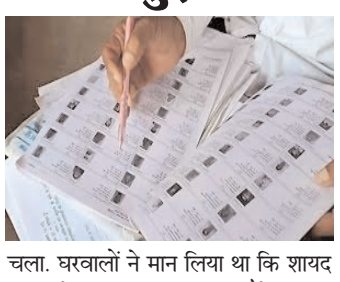

कभी-कभी किस्मत ऐसी पलटी मारती है कि सालों पुराना दर्द भी एक पल में खत्म हो जाता है. कोंडागांव के केशकाल में परिवार के लिए ऐसा ही चमत्कार हुआ, जब 13 साल पहले घर छोड़कर चली गई बेटी अचानक वापस लौट आई. मां-बाप जिन्होंने उसकी राह देखते-देखते उम्र गुजार दी उन्हें यह उम्मीद तक नहीं थी कि वो कभी लौटेगी. लेकिन स्ट्रक्रकी एक औपचारिक जरूरत ने परिवार को एक बार फिर से जोड़ दिया।

2012 में घर छोड़कर चली गई थी सुनीता यादव

परिवारिक तनाव और मनमुटाव के चलते सुनीता यादव वर्ष 2012 में अचानक घर छोड़कर चली गई थी. उस समय किसी को नहीं पता था कि वह कहां गई, कैसी है, जिंदा भी है या नहीं. परिजन ने हर संभव जगह खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. निराश होकर परिवार ने केशकाल थाने में गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वक्त गुजरता गया, 1 साल, 5 साल, फिर 10 साल...लेकिन सुनीता का कोई पता नहीं चला. घरवालों ने मान लिया था कि शायद उनकी बेटी अब कभी घर नहीं लौटेगी।

रायपुर में शादी, बच्चों और परिवार के साथ नया जीवन

इस बीच, सुनीता ने रायपुर में नई जिंदगी शुरू कर दी. वहां उसकी शादी हुई, बच्चे हुए और वह अपने पति व परिवार के साथ जीवन यापन करती रही. लेकिन मायके के लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे।

SIRकी एक जरूरत और किस्मत की अद्भुत वापसी

13 साल बाद कहानी में मोड़ तब आया जब सुनीता को अपने माता-पिता के वोटर आईडी और मतदाता सूची में नाम की जरूरत पड़ी. इसके लिए उसे केशकाल आना पड़ा. और जैसे ही वह अपने पुराने घर पहुंची परिजन उसे देखकर अवाक रह गए. पलभर के लिए किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके सामने खड़ी महिला वही उनकी सुनीता है, जो 13 साल से गायब थी. मां-बाप की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे. सुनीता भी अपने परिवार को इतने सालों बाद देखकर भावुक हो उठी. पूरे गांव में यह खबर फैल गई और लोग इस परिवार की खुशी में शामिल होने के लिए उमड़ पड़े।

गुम इंसान की रिपोर्ट भी हुई बंद

जब सुनीता ने स्थानीय पुलिस के सामने पहचान और जानकारी दी, तो केशकाल थाने में दर्ज पुरानी गुम इंसान रिपोर्ट को बंद कर दिया गया. इससे पुलिस विभाग ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि यह मामला वर्षों से लंबित था।

SIR ने लौटाई मां-बाप की खुशियां

सुनीता के घर लौटने का असली कारण चाहे गलतफहमी का हल हो, या दस्तावेजों की जरूरत पर नतीजा वही निकला जिसका परिवार 13 साल से इंतजार कर रहा था. माता-पिता के चेहरे की मुस्कान और आंखों में खुशी के आंसू बता रहे थे कि कभी-कभी एक औपचारिकता भी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चमत्कार बन जाती है।

संक्षिप्त ख़बरें

दुष्कर्म के मामले में आईआईटी-जोधपुर के प्रोफेसर को 10 साल की सजा, नौकरी का झांसा देकर महिला संग की थी वारदात

नोएडा- उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आईआईटी-जोधपुर के सहायक प्रोफेसर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने उसके ऊपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि यह मामला जून 2019 का है।

राजस्थान के कोटा का रहने वाला है आरोपी

पुलिस के मुताबिक आरोपी विवेक विजयवर्गीय राजस्थान के कोटा का रहने वाला है और वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-जोधपुर में सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी विवेक विजयवर्गीय को वह वर्ष 2000 से जानती थी। वर्ष 2011 में पीड़िता ने विजयवर्गीय के साथ आईआईटी-जोधपुर में लगभग तीन महीने तक साथ में काम किया था।

गेस्ट हाउस में महिला संग आरोपी किया था दुष्कर्म

पीड़िता के अनुसार पांच जून 2019 की शाम को विवेक ने उसे फोन करके बताया कि वह किसी काम से नोएडा आया हुआ है और उसे नौकरी पर चर्चा करने के लिए एक कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया। पीड़िता का आरोप है कि विवेक ने उसे नौकरी का झांसा देकर नोएडा के एक गेस्ट हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के अनुसार उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तथा उसके खिलाफ 25 सितंबर 2019 को पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद सोमवार की शाम को आरोपी विजय को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

न स्कूल न सड़क...35 साल तक लाल आतंक का साया, खौफ इतना कि अफसर तक न आए, आज भी 1980 में जी रहा गांव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बालाघाट पर करीब 35 साल लाल आतंक का साया रहा लेकिन केंद्र सरकार के नक्सलवाद को खत्म करने के लक्ष्य के बाद नीतियों बदली. फोर्स आक्रामक हुई और अब उसके परिणाम आने लगे हैं. अब उम्मीद है कि जल्द ही नक्सलियों का साया बालाघाट के ऊपर से उठ जाएगा. लेकिन जब लाल आतंक के इतिहास को देखा जाए, तो नक्सल प्रभावित गावों के हाल क्या है. जी हां आज भी वह 35 साल पीछे ही रहे गए हैं. सरकार और नक्सलियों की लड़ाई के बीच वो गांव पिस गए, जिन्हें आज के भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए था।

लोकल 18 आदिवासियों और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए काम करने वाले संगठन तथागत फाउंडेशन के साथ उस गांव पहुंची, जहां पर कभी नक्सली अक्सर आते थे या यूं कहें कि नक्सलियों को डेरा यही रहता था. गांव का नाम है केरीकोना, आपको भी इस गांव की कहानी सुननी चाहिए...।

16 घर वाला गांव, जहां कुछ भी नहीं

बालाघाट के दक्षिण बैहर में ज्यादातर गांव पहाड़ों और दर्रो की बीच बसे हैं. कुछ गांव टोली में बसे हुए हैं. उन गांवों में बहुत कम घर और परिवार बसे हुए है. उसी में से एक गांव केरीकोना है, जहां पर सिर्फ 16 घर है. अगर आप आज भी उस गांव में जाना चाहें तो अच्छी सड़क के बाद एक लंबा कच्चा और पथरीला रास्ता तय करना पड़ता है. वहीं, गांव आओ तो अचानक दिखता है एक लकड़ी का बना पुल, जिस पर बांस की बनी एक टाट रखी है. दरअसल, उस गांव में जाने के लिए सड़क तो नहीं है लेकिन गांव में इंटर होने के लिए एक छोटा सा रास्ता है. उस पर भी पुल न था, सालों तक एक पुल की मांग की लेकिन वह नहीं बना ऐसे में गांव वालों ने मिलकर लकड़ी का एक पुल का निर्माण किया है. उस पुल से चौपहिया वाहन नहीं जा सकता था. ऐसे में हमें अपनी गाड़ी को गांव से 100 मीटर दूर खड़े कर पैदल जाना पड़ा।

गांव में न आंगनवाड़ी और न ही स्कूल

ग्रामीणों ने लोकल 18 को बताया कि गांव में आंगनबाड़ी तक नहीं हैं. ऐसे में उन्हें 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता है. वहीं, बारिश के दिनों में तो बच्चे आंगनवाड़ी जा ही नहीं पाते. वहीं, बाकि दिनों गांव का एक शख्स उन्हें आंगनबाड़ी लेकर जाता है. इसके अलावा गांव में स्कूल ही नहीं है. ऐसे में प्राइमरी स्कूल के लिए भी बच्चों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है. मिडिल स्कूल के लिए और भी दूर जाना पड़ता है. ग्रामीणों ने बताया कि छोटे बच्चों को टीकाकरण कभी होता है और कभी नहीं भी होता है. ऐसे में बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं. गांव के बच्चें कुपोषण और चर्म रोग के शिकार भी हो रहे है।

गांव के लोगों ने बनाया लकड़ी का पुल

गांव के लोगों ने सरकार के आने का इंतजार नहीं किया और खुद पहाड़ी खोदकर एक रास्ता भी बनाया और नाले के ऊपर एक लकड़ी का पुल भी बनाया. इस बात को भी तीन साल बीत गए लेकिन उसे अब तक दूरस्त नहीं कराया जा सका है. ऐसे में आज भी गांव के लोगों को कई समस्या का सामना करना पड़ता है. आज भी अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो उन्हें कावड़ बना कर कुछ दूरी तक ले जाना पड़ता है. यहां तक की नेटवर्क भी नहीं मिलता था।

पूर्व सरपंच बोले- न जाने किसकी वजह से पीछे रहे

पूर्व सरपंच बृजलाल वरखड़े गांव की समस्याओं के पीछे नक्सलवाद को भी एक कारण मानते हैं. ऐसे में अधिकारी गांव में नहीं आते थे. लेकिन बीते कुछ सालों में नक्सल समस्या काफी हद तक कम हुई है. ऐसे में गांव की दुर्दशा के लिए अधिकारियों की मेहरबानी है. लगातार आवेदन दिए गए, सालों से दिए जा रहे है लेकिन गांव अब भी विकास राह बाट जो रहा है।

यूपी में एक और BLO की मौत, पत्नी ने कहा- 'अधिकारियों के फोन आते थे...काम का बहुत दबाव था'

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हाथरस- उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां सिकंद्राराऊ क्षेत्र के गांव नावली लालपुर में रहने वाले 40 वर्षीय कमलकांत शर्मा, जो प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक थे और साथ ही बीएलओ (BLO) का काम भी देख रहे थे, की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मौत की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर जिलाधिकारी अतुल वत्स, एसपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा सहित कई अधिकारी पहुंच गए।

काम था ज्यादा दबाव

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह कमलकांत शर्मा घर पर ही अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े। परिवार के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया। लेकिन, अलीगढ़ ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी नीलम शर्मा ने बताया कि कमलकांत पर काम का बहुत दबाव था। अधिकारियों के लगातार फोन आते रहते थे। उन्होंने कई बार पति से कहा भी कि इतना तनाव न लें, लेकिन हालात वैसे ही रहे। सुबह घर की सीढ़ियों से उतरते समय उन्हें चक्कर आया और वे गिर पड़े।

प्रशासन में हड़कंप मचा

घटना की जानकारी मिलते ही सिकंद्राराऊ के एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे और मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी। इसके बाद डीएम और एसपी भी कमलकांत के घर पहुंचे और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ईडी ने बीते दस सालों में 6,000 से अधिक केस दर्ज किए, दोषसिद्धि केवल 120 मामलों में- केंद्र

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों से सामने आया है कि जून 2014 से इस साल अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 6,312 मामले दर्ज किए हैं. हालांकि, इसी अवधि के दौरान एजेंसी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत केवल 120 आरोपियों को सजा दिला सकी. इस संबंध में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोकसभा में दिए गए डेटा के मुताबिक, अगस्त 2019 की शुरुआत से ईडी ने 93 ऐसे मामलों में विशेष पीएमएलए अदालतों के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट भी दायर की, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं बना था. पीएमएलए के 2019 के संशोधन, जो उस वर्ष 1 अगस्त को लागू हुआ था, से पहले जिन मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं बनता था, उन्हें क्षेत्रीय विशेष प्रवर्तन निदेशक की पूर्व स्वीकृति से बंद कर दिया जाता था. 1 जुलाई, 2005 - जब पीएमएलए लागू होना शुरू हुआ - और 31 जुलाई, 2019 के बीच ऐसे 1,185 मामले बंद किए गए।

पश्चिम बंगाल के आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने 1 जून, 2014 - नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद - से 1 नवंबर, 2025 के बीच ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामलों और उनमें दोषसिद्धि की संख्या पूछी थी. इसके जवाब में मंत्री चौधरी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा में सामने आया है कि इस अवधि के दौरान कुल 6,312 मामले दर्ज किए गए और कुल

120 मामलों में दोषसिद्धि हुई.वित्तीय वर्ष 2019-20 से पहले दर्ज मामलों की संख्या 200 तक नहीं पहुंची थी या उससे अधिक नहीं थी, लेकिन उस वित्तीय वर्ष के दौरान यह 557 तक पहुंच गई. 2020-21 में यह बढ़कर 996 हो गई और 2021-22 में इसकी संख्या 1,116 हो गई. इसके बाद पूरे एक साल में इसमें कमी तो आई, लेकिन यह संख्या कभी भी 700 से कम नहीं हुई।

सिन्हा ने यह भी पूछा कि क्या यह सच है कि '49 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?' इससे पहले चौधरी ने जुलाई में संसद में दिए गए एक जवाब में कहा था कि ईडी ने 1 नवंबर, 2015 से 30 जून, 2025 के बीच विशेष पीएमएलए अदालतों में उसी अवधि के दौरान दर्ज मामलों में से 49 क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थीं. सिन्हा के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने सोमवार (1 दिसंबर) को कहा कि 1 अगस्त, 2019 से ईडी ने 93 ऐसे मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं बनता था।

मंत्री के जवाब में इसके लिए 'विभिन्न कारणों' को जिम्मेदार ठहराया गया, जैसे कि अपराध को जिस मामले में सूचीबद्ध किया गया था, उसे बंद करना. ऐसे मामले जहां अदालत को पीएमएलए के तहत परिभाषित (सूचीबद्ध) अपराध से संबंधित कोई अपराध नहीं मिला, संबंधित अपराध के मामले को रद्द करना आदि. हालांकि, ईडी द्वारा निर्दिष्ट विशेष अदालतों के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पीएमएलए में संशोधन किए जाने से पहले 14 वर्षों में इसने 1,185 ऐसे मामले बंद कर दिए थे जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं बनता था।

ज्ञात हो कि ईडी को पुलिस या किसी अन्य एजेंसी द्वारा पीएमएलए के संदर्भ में 'प्रेडिकेट ऑफेंस' के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करने का अधिकार है. पीएमएलए के भाग ए और सी में वर्णित अपराधों को सूचीबद्ध (scheduled) अपराध कहा जाता है. मोदी सरकार ने पीएमएलए में संशोधन करके इसकी शक्तियों का विस्तार किया है, जिसके तहत अन्य बातों के अलावा आरोपी व्यक्तियों को ज़मानत पाने के लिए प्रथमदृष्टया अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी. आलोचकों का कहना है कि पीएमएलए एजेंसी का दुरुपयोग भाजपा के राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय का 2022 का फैसला, जिसमें संशोधनों को बरकरार रखा गया था, जो बेहद विवादास्पद रहा. शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ वर्तमान में अपने फैसले को चुनौती देने पर विचार कर रही है.इस साल की शुरुआत में अदालत की एक पीठ ने इस बात पर गौर किया था कि एजेंसी ने जितने मामले दर्ज किए हैं, उनकी तुलना में उसे कम सजाएं मिली हैं. इसी तरह राजनेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की तुलना में उन्हें दोषसिद्धि दिलाने की संख्या भी कम है।

स्वच्छ भविष्य का संकल्प: प्रदूषण नियंत्रण की राह में चुनौतियाँ

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हमारे सामूहिक इतिहास का वह आइना है जिसमें हम विकास की अंधी दौड़ के पीछे छूटे मानव जीवन, पर्यावरण और नैतिकता की कीमत को साफ़-साफ़ देख सकते हैं। हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस सिर्फ कैलेंडर की एक औपचारिक तारीख नहीं, बल्कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की स्मृति में दर्ज एक गहन चेतावनी है–एक ऐसी चेतावनी जिसकी गूँज आज भी हवा, पानी, मिट्टी और मानव शरीर के भीतर तक सुनाई देती है। त्रासदी की उस भयावह रात को चार दशक से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से जन्मी पीड़ा आज भी भोपाल की गलियों में, अस्पतालों के दस्तावेजों में और पीढ़ियों की थकान में दर्ज है। दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिने जाने वाले इस विषाक्त प्रसंग ने न सिर्फ हजारों लोगों की जान ली, बल्कि उद्योग, सरकार और समाज–तीनों को यह सबक दिया कि निगरानी की एक चूक, लापरवाही की एक परत और मुनाफे की एक अंधी चाह किस तरह मानव सभ्यता को भीतर से झकझोर सकती है। इस दिन की सार्थकता इसी बिंदु से शुरू होती है। आधुनिक भारत, जो खुद को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, वह तभी सुरक्षित और स्थायी भविष्य का दावा कर सकता है जब विकास का आधार पर्यावरणीय संवेदनशीलता और मानवीय गरिमा पर स्थापित हो। आज स्थिति यह है कि देश के अनेक शहर लगातार वर्ष दर वर्ष दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल होते रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, पटना, कानपुर, गुड़गांव जैसे शहरों में PM2.5 और अन्य प्रदूषकों का स्तर न सिर्फ राष्ट्रीय मानकों, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमाओं से भी कई गुना अधिक पाया जा रहा है। यह केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है; यह एक जनस्वास्थ्य आपातस्थिति है। श्वसन रोगों, हृदय विकारों, कैंसर और समयपूर्व मौतों के बढ़ते आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि हम अपने ही जीवन-सहचर वातावरण को धीरे-धीरे विषैला बना चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों की रिपोर्टें लगातार आगाह करती रही हैं कि वायु प्रदूषण वैश्विक स्तर पर हर वर्ष लाखों मौतों का कारण बन रहा है और भारत इसमें सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। सरकारी नीतियों और कानूनी प्रावधानों की बात करें, तो भारत में वायु एवं जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और राष्ट्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का ढांचा वर्षों से मौजूद है। इन कानूनों का उद्देश्य उद्योगों और अन्य स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना, मानक तय करना तथा उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई सुनिश्चित करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) जैसे व्यापक मिशन की घोषणा की है, जिसने 2024 तक कण प्रदूषण को 20-30% तक कम करने का लक्ष्य रखा था। साथ ही BS-VI उत्सर्जन मानक, निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली, और देशभर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरूआत इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। लेकिन सफलता का मापदंड काग़ज़ी नीतियों या घोषणाओं में नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले परिवर्तनों में निहित होता है। और यहीं यह चिंता उभर कर सामने आती है कि क्रियान्वयन की इच्छाशक्ति और व्यवस्थागत पारदर्शिता अब भी अधूरी है। कई उद्योग मानकों का उल्लंघन करते हैं, कचरा निपटान में अनियमितता बरकरार है, और शहरी नियोजन की कमजोरियाँ प्रदूषण के नए स्रोत तैयार करती रहती हैं। इस पृष्ठभूमि में नागरिकों की भूमिका कहीं अधिक महत्व रखती है। प्रदूषण नियंत्रण केवल कानूनों का विषय नहीं, बल्कि जीवनशैली और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रश्न है। जब तक लोग ऊर्जा की बचत, अनावश्यक वाहन उपयोग में कमी, सार्वजनिक परिवहन और कार-शेयरिंग को प्राथमिकता, कचरे का जिम्मेदाराना प्रबंधन, प्लास्टिक उपयोग में कटौती, और स्थानीय स्तर पर सफाई-अभियानों में भागीदारी जैसे छोटे-छोटे कदम नहीं अपनाएँगे, तब तक कोई भी सरकारी योजना सीमित ही प्रभाव डाल पाएगी। पर्यावरणीय संकट की जड़ें अक्सर व्यक्तिगत आदतों में छिपी रहती हैं–एसी का तापमान, घरों से निकलने वाला कचरा, प्लास्टिक पर निर्भरता, और यहां तक कि सोशल मीडिया पर पर्यावरणीय विषयों के प्रति उदासीनता भी इस संकट को गहरा बनाती है।

समाज के अन्य संस्थानों की भूमिका भी निर्णायक है। स्कूलों और महाविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को केवल एक औपचारिक विषय के रूप में नहीं, बल्कि व्यवहार में लाने योग्य जीवन-कौशल के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे और युवा वही अपनाते हैं जो समाज उन्हें जीकर दिखाता है; इसलिए शिक्षण संस्थानों को स्वयं 'ग्रीन कैंपस' बनने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। मीडिया को भी प्रदूषण को 'मौसमी' खबर या किसी विशेष शहर की समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय संकट के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। उद्योगों और वैज्ञानिक समुदाय को नवाचारों और तकनीकी संशोधनों के माध्यम से प्रदूषण-नियंत्रित विकास मॉडल का निर्माण करना होगा ऐसा मॉडल जो ऊर्जा दक्षता और औद्योगिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हमें यह याद दिलाता है कि किसी भी समाज

की प्रगति केवल ऊँची इमारतों, विस्तृत सड़कों या बढ़ते उत्पादन से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वहां हवा कितनी शुद्ध है, पानी कितना सुरक्षित है, मिट्टी कितनी उपजाऊ है और मनुष्य कितना स्वस्थ है। भोपाल गैस त्रासदी केवल इतिहास की घटना नहीं; यह उस विकास-दृष्टि का परिणाम थी जो मानवीय मूल्यों और पर्यावरणीय संतुलन को पीछे धकेल देती है। यदि हम वास्तव में एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य की कल्पना करना चाहते हैं, तो हमें वही गलती दोहराने की अनुमति खुद को नहीं देनी होगी। आज हमें यह दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी कि विकास की हर दिशा मानवीय गरिमा, पारिस्थितिक संतुलन और जीवन के प्रति सम्मान से संचालित होगी। यह भी संकल्प लेना होगा कि सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक जगत और आम नागरिक मिलकर उस धरती की रक्षा के लिए एकजुट हों, जिसने हमें जन्म दिया और पोषित किया है। जब यह संकल्प नीतियों में, व्यवहार में और सामूहिक चेतना में रूपांतरित होगा, तभी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस एक वार्षिक स्मरण से आगे बढ़कर सचमुच भविष्य-निर्माण का आधार बनेगा।

महेन्द्र तिवारी

बायजूज़ का सबक: तकनीक नहीं, भरोसा ही शिक्षा का असली आधार है

[जब शिक्षा लोन में बदली और सपने ईएमआई में क़ैद हुए]

[बिना नींव की ऊँचाई: भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए सबक]

भारत के सबसे चमकते एडटेक सितारे की दास्तान अब अपनी अंतिम साँसें गिन रही है। बायजूज़–जिसकी वैल्यूएशन कभी 22 अरब डॉलर की चकाचौंध में दमकती थी–आज दिवालिया प्रक्रियाओं के हवाले हो चुका है। नवंबर 2025 तक कंपनी पर कई हजार करोड़ रुपये का नुकसान और देनदारी का बोझ लद चुका है, कई हजार कर्मचारी बेरोज़गारी की खाई में धकेल दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्टों और उपभोक्ता शिकायतों के अनुसार, लाखों अभिभावकों की मेहनत की कमाई अनिश्चितता के जाल में फँसी हुई है। यह केवल एक स्टार्टअप का ढहना नहीं; यह पूरे एडटेक उद्योग के भीतर गूँजती चेतावनी है–अति-आत्मविश्वास की अंधी दौड़, आक्रामक बिक्री की खतरनाक संस्कृति और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की असहनीय लापरवाही, जो अंततः एक सामूहिक विफलता का महाभारत रच बैठी। सब कुछ 2015 में एक बेहद सरल-सा विचार बनकर उभरा था। बायजू रविंद्रन ने बच्चों को वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाने का बीज बोया, और कोविड-19 के अंधकारमय दिनों में यह बीज देखते ही देखते एक वृक्ष की तरह फैल गया। 2020-21 में जब स्कूलों के गेट बंद थे, अभिभावक अपनी संतानों की पढ़ाई बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ठीक इसी नाजुक घड़ी में बायजूज़ ने सबसे आक्रामक और नैतिकता-तोड़ सेल्स रणनीतियाँ अपनाईं–टेलीमार्केटिंग कॉलों में दबाव का पहाड़, 'अभी नहीं लिया तो बच्चे का साल डूब जाएगा' जैसे डरावने वाक्यों की बौछार, और कई परिवारों के लिए तो बिना स्पष्ट जानकारी दिए शुरू कर दी गई ईएमआई जैसी अदृश्य जंजीरें। सर्वे दर्शाते हैं कि 2021-22 में कंपनी ने कोर रेवेन्यू ?3,550 करोड़ और कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू ?5,000 करोड़ के आँकड़े पेश किए–पर इन चमकदार संख्याओं के पीछे छिपा सच कहीं अधिक काला था। इस राजस्व का बड़ा हिस्सा उन लोन से उपजा था, जो बाद में लगभग पूरी तरह अशोधित साबित हुए–ऐसे लोन, जिन्होंने हज़ारों परिवारों को आर्थिक अस्थिरता, टूटते भरोसे और गहरे भावनात्मक तनाव की अँधेरी खाई में धकेल दिया। वैल्यूएशन की चकाचौंध भरी दौड़ में बायजूज़ ने 2021-22 में एक के बाद एक दर्जन से अधिक कंपनियाँ निगल लीं–व्हाइटहैट जूनियर हो, टॉपर, ग्रेट लर्निंग आदि–हर अधिग्रहण कई गुना तक की अविश्वसनीय वैल्यूएशन पर। प्रॉसस, चान-ज़करबर्ग इनिशिएटिव और ब्लैकरॉक जैसे दिग्गज निवेशक मानो आँख बंद करके धन उलीचते रहे, जबकि अंदर ही अंदर कंपनी दीमक की तरह खोखली होती जा रही थी। 2021-22 के ऑडिटेड वित्तीय दस्तावेज़ पूरे 22 महीने की देरी से सामने आए–और जैसे ही आए, निवेशकों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पता चला कि राजस्व का विशाल हिस्सा 'अक्रुअल बेसिस' पर दिखाया गया था–यानी जो पैसा कभी आया ही नहीं, उसे भी कमाई मानकर बैलेंस शीट चमकाई गई। 2023-24 में जब प्रॉसस ने क्रमिक रूप से वैल्यूएशन को शून्य घोषित किया, तभी यह बुलबुला जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ा। लेकिन इस पतन की सबसे मार्मिक कीमत कर्मचारियों और शिक्षकों ने चुकाई। 2022 से अब तक पाँच बार बड़े पैमाने पर छँटनी हुई, सैकड़ों नहीं–हज़ारों लोग एक झटके में सड़क पर आ गए। बहुतों को तीन-तीन महीने तक वेतन तक नहीं मिला। जिन शिक्षकों ने वर्षों तक अपनी ऊर्जा, अपनी पहचान इस संस्था में समर्पित की, उन्हें एक सूचना भर में बेरोजगार कर दिया गया। अभिभावकों की त्रासदी इससे भी भयावह है। लाखों परिवारों ने 1-2 लाख रुपये तक खर्च कर कोर्स खरीदे–पर अब अधिकांश के लिए प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचना भी संभव नहीं। कई बच्चों ने तो कोर्स शुरू भी नहीं किया, फिर भी बैंक लगातार ईएमआई काट रहा है। उपभोक्ता मंचों पर शिकायतें हजारों नहीं, बल्कि लाखों में दर्ज हैं–हर शिकायत एक टूटे हुए भरोसे की, एक ठगे गए सपने की और एक असहाय परिवार की गवाही बनकर खड़ी है। इस पूरे संकट की मूल में तीन बड़े कारण हैं। पहला - कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूर्ण अभाव। प्रमोटर दंपति, बायजू और दिव्या गोकुलदास, कंपनी को मानो अपनी निजी चेकबुक और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का विस्तार मानकर चलाते रहे। दूसरा–निवेशकों का अनियंत्रित लालच, जिसने उचित जाँच-पड़ताल को हाशिये पर धकेल दिया। और तीसरा–नियामक तंत्र की चुप्पी, जिसकी कीमत आज लाखों परिवार चुका रहे हैं। न सेबी ने समय रहते आवाज उठाई, न आरबीआई ने लोन स्ट्रक्चर पर रोक लगाई, और न शिक्षा मंत्रालय ने उस क्षेत्र में दखल दिया जो सीधे बच्चों की ज़िंदगी को प्रभावित करता था। इस त्रासदी से कुछ कड़े सबक सीखने होंगे। पहला, एडटेक कंपनियों के लिए एक स्वतंत्र और मजबूत नियामक ढाँचा तुरंत विकसित होना चाहिए, जिसमें रिफंड नीतियों से लेकर सेल्स रणनीतियों और विज्ञापनों तक हर चीज़ पर कठोर नियम लागू हों। दूसरा–स्कूल शिक्षा को एक 'उत्पाद' की तरह बेचने की सोच बदलनी होगी; शिक्षा सेवा है, सौदा नहीं। तीसरा–निवेशकों को यह समझना होगा कि 200 गुना वैल्यूएशन पर पैसा फेंकना इनोवेशन नहीं, मूर्खता है; निवेश से पहले बुनियादी सवाल पूछना ही बुद्धिमानी है। चौथा–अभिभावकों को यह भी स्वीकारना होगा कि किसी भी चमकदार ऐप से अधिक कद बच्चे की मेहनत और शिक्षक के समर्पण का होता है। बायजूज़ का पतन भारतीय स्टार्टअप परिदृश्य के लिए एक तीखा स्मरण है: ऊँचाई पर पहुँचना आसान है, पर बिना मजबूत नींव के टिक पाना असंभव।

यह उम्मीद की जानी चाहिए कि एनसीएलटी प्रक्रिया (नेशनल कम्पनी लॉ ट्राइब्यूनल) कम से कम अभिभावकों और कर्मचारियों के लिए कुछ राहत लेकर आएगी। लेकिन इस कहानी का असली महत्व उस सीख में है, जिसे अगले दशक तक देश को याद रखना होगा कि चमकदार विज्ञापन, गगनचुंबी वैल्यूएशन और आक्रामक वादों के पीछे छिपी सच्चाई को परखना हर निवेशक, हर अभिभावक और हर नियामक का नैतिक कर्तव्य है। बायजूज़ का अध्याय शायद समाप्त हो जाए, पर उसकी गलतियों से उपजा अनुभव भारतीय एडटेक के लिए एक नए, अधिक ज़िम्मेदार और अधिक मानवीय भविष्य की नींव बन सकता है।

प्रो. आरके जैन

आज का हर मानव अर्जुन है, और गीता उसका कृष्ण

मानव जीवन का हर चरण एक नए कुरुक्षेत्र की तरह सामने खड़ा होता है-संघर्षों, दुविधाओं और निर्णयों से भरा हुआ। परिस्थितियाँ बदलती हैं, युग बदलते हैं, साधन बदलते हैं, पर मनुष्य का मूल संकट वही रहता है: क्या सही है, क्या कर्तव्य है, क्या चुनें, कैसे चलें? यही मन की वह स्थिति है जिसमें आज का हर मनुष्य कहीं न कहीं संकोच और भ्रम से ग्रस्त, कर्तव्य और मोह के बीच डांवाडोल अर्जुन बन जाता है और ऐसे हर क्षण पर गीता उसकी कृष्ण बनकर सामने आती है, मार्ग दिखाती है, मन को स्थिर करती है, और जीवन-दर्शन के सत्य को उजागर करती है। कुरुक्षेत्र की भूमि किसी दूर अतीत की स्मृति मात्र नहीं; वह हर उस क्षण में जीवित है जब मनुष्य अपने निर्णयों के भार से दब जाता है। अर्जुन का धनुष आज के जीवन में हर भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के हाथ में है, फिर चाहे वह विद्यार्थी हो, परिवार का सदस्य, कर्मचारी, नेता, व्यापारी ,उद्यमी, किसान या नागरिक। मोह, अपेक्षाएँ, भ्रम, दबाव और परिणामों की चिंता व्यक्ति को उसी तरह विचलित करती है जैसे अर्जुन युद्ध के द्वार पर विचलित हुआ था। ऐसे समय में गीता का यह संदेश कि कर्म मनुष्य के हाथ में है, फल नहीं,आज के अनिश्चित, प्रतियोगी और तनाव से भरे वातावरण में मानसिक संतुलन की सबसे बड़ी कुंजी है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि व्यक्ति प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करे, परिणाम पर नहीं। कर्मयोग का सिद्धांत आज के कार्यस्थल में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। आसक्ति रहित कर्म करने का विचार 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' (इमोशनल इंटेलिजेंस), 'कार्य-जीवन संतुलन' (वर्क-लाइफ बैलेंस) और 'मानसिक स्वास्थ्य' (मेंटल वेल-बीइंग) के आधुनिक सिद्धांतों से कहीं अधिक गहरा और व्यावहारिक है। गीता का यह संदेश कि मनुष्य कर्म करते समय जितना अपेक्षाओं और अहंकार से मुक्त होगा , वह उतना ही अधिक संतुलित और सफल होगा, गीता को केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन-प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ संदर्भ ग्रंथ स्थापित करती है। कृष्ण अर्जुन से संवाद करते हुए न आदेश देते हैं, न दबाव बनाते हैं; वे तो अर्जुन की मन:स्थिति को समझते हुए उसके भ्रम का धैर्यपूर्वक समाधान करते हैं, और उसे कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के प्रभावी नेतृत्व की कसौटियाँ जैसे सहानुभूति, जागरूकता, संवाद और प्रेरणा आदि सभी आदर्श रूप में कृष्ण-अर्जुन संवाद में देखने को मिलती हैं। आधुनिक प्रबंधन में 'रूपांतरणकारी नेतृत्व' (ट्रांसफ़ॉर्मेशनल लीडरशिप) का जो सिद्धांत पढ़ाया जाता है, वह गीता के नेतृत्व दर्शन का ही आधुनिक रूप है। अविश्वसनीय लेकिन सत्य यह है कि गीता का मनोवैज्ञानिक पक्ष आज विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण, मन की स्थिरता, विचारों का अनुशासन और ध्यान का अभ्यास आधुनिक मनोचिकित्सा में संज्ञानात्मक चिकित्सापद्धति (कॉग्निटिव थेरेपी) और सचेतन ध्यान (माइंडफुलनेस) के रूप में उपयोग किए जाते हैं। 'स्थितप्रज्ञ' का आदर्श उस व्यक्ति की छवि है जो परिस्थितियों के उतार-चढ़ाव में भी संतुलित रहता है; आज की भाषा में यही धैर्य-सामर्थ्य (रेज़िलिएंस) और भावनात्मक स्थिरता (इमोशनल स्टैबिलिटी) है। गीता का धर्म संकीर्ण धार्मिकता नहीं, बल्कि कर्तव्य और नैतिकता का विज्ञान है। यह बताता है कि सही वही है जो व्यापक हित और सत्य पर आधारित हो। आज जब समाज मूल्य-संकट, भ्रष्टाचार, नैतिक भ्रम और आत्मकेंद्रित प्रवृत्तियों से जूझ रहा है, गीता का यह उपदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को पहचानकर, सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। यही संदेश अर्जुन को दिया गया था, और वही संदेश आज के मानव को चाहिए। गीता की प्रासंगिकता का वैश्विक प्रभाव और स्वीकारता इसे और भी अधिक प्रमाणिक ग्रंथ स्थापित करती है। गांधी से लेकर आइंस्टीन और ओपेनहाइमर तक, विश्व के अनेक महान विचारकों ने गीता से प्रेरणा ली। भारत सहित रूस, फ्रांस, अमेरिका तथा जापान तक में गीता पर शोध होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। हार्वर्ड, एम.आई.टी. और अन्य वैश्विक विश्वविद्यालयों में गीता को नेतृत्व, नैतिकता और मनोविज्ञान के संदर्भ में पढ़ाया जा रहा है। यह अपने आप में सिद्ध करता है कि गीता किसी विशेष समुदाय की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की ज्ञान-पुस्तक है। आज का मानव अतीत से अधिक तनाव, असंतुलन और

अनिश्चितता का सामना कर रहा है। भविष्य की चिंता और अतीत का भार उसके वर्तमान को खोखला तक कर देता है। ऐसे विषम परिस्थितियों में गीता उसे यह कला सिखाती है कि वर्तमान में कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे संतुलित रखा जाए, और कैसे अपने भीतर के अर्जुन को शक्ति प्रदान की जाए। यही कारण है कि गीता आज केवल प्रासंगिक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य हो उठती है। अंततः सत्य यही है कि जीवन के विविध मोड़ पर मनुष्य कभी न कभी अर्जुन बन जाता है(दुविधाग्रस्त, प्रश्नों से भरा, निर्णयों से विचलित) और ऐसे कठिन समय में हर बार गीता उसके सामने कृष्ण बनकर खड़ी हो जाती है(सत्य, विवेक और कर्तव्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए)। यही कारण है कि गीता आज भी जीवित है, प्रासंगिक है, और मानव जीवन की सबसे स्थायी दिशा-दर्शक प्रकाश किरण है।

डा मनमोहन प्रकाश

संपादकीय

शुभ है सनातन आस्था को सामाजिक शक्ति बनाने का निर्णय

इक्कीसवीं सदी की एक चौथाई हिस्से का नवंबर माह सांस्कृतिक रूप से ऐतिहासिक रहा। इस माह तीन ऐसी उल्लेखनीय बातें हुई है जिन्होंने भविष्य में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और सनातन धारा के निरंतर प्रवहमान रखने की महत्वपूर्ण भूमिका लिख दी है। 25 नवंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राममंदिर में धर्मध्वजा का वैभव लहराया तो 28 नवंबर गोवा के श्री संस्थान गोकरण पार्टागली जीवोत्तम मठ परिसर में भगवान राम की विश्व की सबसे ऊंची 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसी सप्ताह बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी कर राज्य के सभी मंदिरों और मठों में हर माह पूर्णिमा को सत्यनारायण कथा तथा अमावस्या को भगवती पूजा का आयोजन करने का निर्णय लिया। एक दशक पहले तक भारतीय राजनीति में ऐसा वातावरण था कि हिंदुत्व या सनातन संस्कृति की बात करना राजनीतिक वर्गों के लिए जोखिम भरा कदम माना जाता था। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में बहुसंख्यक समाज की धार्मिक परंपराओं की उपेक्षा करना राजनीति का सहज सूत्र बन गया था। किंतु बीते वर्षों में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ बदली हैं। केंद्र तथा विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में नीतिगत परिवर्तनों ने एक ऐसा वातावरण बनाया जिसमें हिंदू समाज के प्रश्नों और उसकी सांस्कृतिक विरासत को पुनः सम्मान मिला। इसी क्रम में बिहार सरकार का हालिया निर्णय ऐतिहासिक महत्व रखता है। बिहार के मंदिरों और मठों में पूर्णिमा को सत्यनारायण कथा तथा अमावस्या को भगवती पूजा का आयोजन परोक्ष रूप से राष्ट्रव्यापी धार्मिक चेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ सामाजिक एकता का खाका है। इस उद्देश्य से प्रत्येक जिले में विशेष जिला समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे, जो धार्मिक गतिविधियों के सुचारु संचालन, पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करेंगे। न्यास बिहार में मंदिर परिसरों में अखाड़ों के लिए स्थान आवंटित करने की नीति पर भी काम कर रहा है। इसका उद्देश्य मंदिरों को केवल पूजा के स्थल तक सीमित रखने के बजाय उन्हें सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र में परिवर्तित करना है। मंदिर भारतीय समाज में सदियों से केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद का भी केंद्र रहे हैं। सत्यनारायण कथा, भगवती पूजा, यज्ञ, प्रवचन, स्वास्थ्य शिविर, पारंपरिक खेलकूद–इन सभी गतिविधियों को पुनः संरचित रूप में विकसित करने का उद्देश्य समाज में सामूहिकता, समरसता और सामाजिक पूंजी को सुदृढ़ करना है। इस धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा के महीने में दो बार सामूहिक आयोजनों से जाति-भेद, सामाजिक दूरी और विभिन्न समुदायों के बीच बनी खाई पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मंदिर भारतीय समाज के लिए केवल प्रार्थना-स्थल नहीं, बल्कि मूल्य, परंपरा, कला, शिक्षा और सामाजिक व्यवहार का केंद्र रहे हैं। भारतीय चिंतन परंपरा के विख्यात चिंतक वासुदेव शरण अग्रवाल 1930 में लिखे निबंध 'सत्यनारायण व्रत कथा' में कहते हैं। 'हिंदू जाति में बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी व्यक्ति ऐसा न होगा, जिसने सत्यनारायण-व्रत-कथा न सुनी हो। जीवन के शुभ-अशुभ दोनों कालखंड में सत्यनारायण कथा जा अपना वैशिष्ट्य है' सत्यनारायण कथा का फैलाव इतना रहा है कि फिजी-मॉरिशस से लेकर दक्षिणी अमेरिका तक फैले भारतीयों और यूरोप-अमेरिका के अमीर सनातनी भारतीय घरों में भी यह होती रही है। मार्क्सवादी सिनेमाकार ऋत्विक घटक तक ने माना है: 'इस देश की संस्कृति के चरित्र और विशिष्टता का ठीक से अध्ययन तभी किया जा सकता है जब भारत के भाववाद को उसके दर्शन और धर्म के साथ परख कर और तौल कर समझा जाए।' सत्यनारायण कथा और भगवती पूजा जैसे आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि लोक-जीवन की सामूहिक स्मृति हैं–वह स्मृति जो उपेक्षा के कारण धूमिल हो रही थी। इस निर्णय से वे परंपराएँ पुनः समाज की धड़कन बन सकेंगी। सत्यनारायण कथा एवं भगवती पूजा प्राचीन काल से सुख-समृद्धि और शक्ति के प्रतीक रही हैं; इन्हें पुनर्जीवित करना सांस्कृतिक आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना है। जब शासन सांस्कृतिक उन्नयन के साथ खड़ा होता है, सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व देता है तो परंपराएँ केवल जीवित नहीं रहतीं–वे विकसित होती हैं और समाज को सशक्त बनाती हैं, समाज अधिक संगठित,आत्मविश्वासी और प्रगतिशील बनता है। भारतीय राजनीति में लंबे समय तक ऐसी प्रवृत्तियाँ देखी गई जिनमें धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या बहुसंख्यक समाज की धार्मिक परंपराओं की उपेक्षा से जुड़ गई थी। कई दशक तक हिंदू मान्यताओं, ग्रंथों और देवताओं पर प्रश्न उठाना प्रगतिशीलता का पर्याय माना गया। रामायण और महाभारत को काल्पनिक, भगवान राम और कृष्ण को मात्र मिथक सिद्ध करने के प्रयास लगातार किए गए। इसके विपरीत, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीतियों के तहत वर्षों तक हज सब्सिडी दी गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में समाप्त करने का निर्देश दिया। कई राज्यों–जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और बिहार–में इमामों तथा उनके सहायकों को सरकारी वेतन तक प्रदान किया गया, जबकि बहुसंख्यक समाज के पुरोहितों, पुजारियों या मंदिर कर्मियों के लिए ऐसी कोई संरचना उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार, छात्रवृत्ति योजनाओं में भी अक्सर सामुदायिक आधार पर भेदभाव देखा गया, जहाँ मेधावी एवं वंचित बहुसंख्यक छात्रों की तुलना में औसत प्रदर्शन वाले अल्पसंख्यक छात्रों को प्राथमिकता दी जाती रही। अब पानी बहुत बह चुका है,धाराओं ने अपनी दिशा बदल दी है। वैश्वीकरण के दौर में विश्व की अनेक सभ्यताएँ अपनी जड़ों की ओर वापसी की आवश्यकता महसूस कर रही हैं। ऐसे में अयोध्या में धर्मध्वजा, गोवा में श्रीराम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना और बिहार के मठ-मंदिरों में पूर्णिमा और अमावस्या को सत्यनारायण कथा और भगवती पूजा भारत की सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का सशक्त और शुभ संकेत है।

हरीश शिवनानी

सदन बनाम शोर,शीतकालीन सत्र की पहली भोर

राजनीतिक टकराव और संवाद की नयी चुनौती

शीतकालीन सत्र हमेशा से राजनीतिक तापमान का आईना माना जाता रहा है। वर्ष के अंतिम महीने में जब केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों और नीतिगत प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, तब विपक्ष इसे जवाबदेही और जनहित के मुद्दों को उठाने के अवसर के रूप में देखता है। इसी उम्मीद और उत्सुकता के बीच 1 दिसंबर से आरंभ हुआ संसद का यह शीतकालीन सत्र, अपने पहले ही दिन उस सौहार्द्र और गंभीरता से दूर दिखाई दिया जिसकी एक लोकतांत्रिक संस्था से अपेक्षा की जाती है।पहले दिन राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कारण वही पुराना-हंगामा, नारेबाजी और तीखी राजनीतिक तल्खी। सत्र शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को एक स्पष्ट संदेश दिया कि संसद का मंच राजनीति की लड़ाई का एरिना नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों पर काम करने का स्थान है। उनकी टिप्पणी, सदन में ड्रामा नहीं, डिलेवरी चाहिए, में सिर्फ राजनीतिक व्यंग्य नहीं था, बल्कि कार्यसंस्कृति पर गंभीर चिंता का संकेत भी झलक रहा था।मोदी ने विपक्ष से यह भी कहा कि चुनाव परिणामों में पराजय मिलना राजनीतिक जीवन का अंग है, लेकिन पराजय की निराशा में डूबकर सदन को ठप कर देना लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार ट्रिप्स जैसी बहसों और विधायी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन यह तभी संभव है जब विपक्ष मजबूत मुद्दे उठाए और सहयोग की भावना दिखाए।अचानक इस्तीफे पर राजनीति का बवंडर तेज हुआ।सत्र की शुरुआत से पहले ही एक बड़ा राजनीतिक तूफ़ान उस वक्त खड़ा हो गया जब राज्यसभा के पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति जैसे पदों को संभाल चुके धनखड़ के इस निर्णय ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे असामान्य कदम बताते हुए सवाल किया कि इतनी बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी छोड़ने के पीछे कौन-सा दबाव या परिस्थिति रही होगी। खड़गे की टिप्पणी पर भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर खड़गे जी को इस विषय में बहुत तकलीफ हो रही है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह बयान दर्शाता है कि आने वाले दिनों में सत्ता और विपक्ष के बीच वाद-विवाद कैसे मोड़ ले सकता है।सत्र का एजेंडा बड़ा, लेकिन माहौल गर्म है।शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित होना है। कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं और सरकार लगभग 10 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें तंबाकू और पान मसाला पर सेस लगाने वाला बिल, दिवाला कानून में सुधार, और जनविश्वास संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव शामिल हैं। संसदीय समितियों को भी कई रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने एसआईआर मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। इससे सरकार के विधायी कार्यक्रम पर अनिश्चितता के बादल मंडराते नजर आए। सरकार का आरोप है कि विपक्ष बिना पर्याप्त चर्चा के सिर्फ बाधा उत्पन्न करने की रणनीति अपना रहा है। वहीं विपक्ष कहता है कि उसके सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा और सरकार संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा से बच रही है।प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में हो रहे व्यवधानों पर स्पष्ट अपील की।मेरी चिंता यह है कि सदन चले। जनता हम सब से काम की उम्मीद करती है।

नए सभापति का स्वागत और पुरानी राजनीति की छाया

सत्र की शुरुआत में सी.पी. राधाकृष्णन को राज्यसभा के नए सभापति के रूप में स्वागत किया गया। मोदी ने उनके अनुभव की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में सदन की कार्यवाही अधिक गरिमामय और प्रभावी होगी। लेकिन स्वागत समारोह के माहौल में भी दलगत राजनीति की तल्खी कम नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खड़गे पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति के लिए अनुचित शब्द बोले। यह आरोप भी सत्र के शुरुआत में तनाव का एक और सूत्र बन गया।विपक्ष के भीतर भी समानता नही लेकिन भिन्न आवाजेंसुनाई दी।हंगामे के इस माहौल में विपक्ष के भीतर भी अलग-अलग स्वर सुनाई दिए। गोगोई ने कहा कि अगर विपक्ष के मुद्दों को सत्र में उचित स्थान और चर्चा मिले, तो वे सरकार के सभी विधेयकों पर सहयोग करने को तैयार हैं। यह बयान संकेत देता है कि विपक्ष की मंशा केवल हंगामा करना नहीं है, बल्कि बहस और संवाद भी चाहता है।यदि उसे सम्मानजनक अवसर मिले। हालाँकि, इस बीच राहुल गांधी सदन से उस समय बाहर निकल गए जब कार्यवाही हंगामे के कारण रुकावट का सामना कर रही थी। यह घटना भी राजनीतिक व्याख्याओं का विषय बनी।इस बीच चिराग पासवान ने कहा कि हंगामा छवि चमकाता है, काम नहीं,लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने विपक्ष के विरोध को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की।हंगामा करने वाला अपनी छवि चमकाता है, लेकिन काम नहीं करता। पासवान के इस वक्तव्य ने सत्ता पक्ष की उस भावना को मजबूत किया, जिसमें वे कहते हैं कि विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रहा है और संसद के संचालन में बाधा डाल रहा है।

हंगामा बनाम लोकतंत्र

सत्र के पहले दिन जिस प्रकार कार्यवाही बाधित हुई, उसने इस विवाद को फिर जन्म दिया कि क्या लगातार हंगामे के माध्यम से विपक्ष अपनी भूमिका को कमजोर कर रहा है, या यह उनके लिए मजबूरी है क्योंकि सरकार उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं देती?सत्ता पक्ष का तर्क है कि हंगामा लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। संसद बहस, विचार और नीतिगत विमर्श का स्थान है, और लगातार व्यवधान से न सिर्फ विधायी कामकाज रुकता है, बल्कि जनता का विश्वास भी डगमगाता है।विपक्ष का दावा है कि संवेदनशील मुद्दों पर सरकार की चुप्पीऔर अड़ियल रवैया उन्हें कठोर कदम उठाने पर मजबूर करता है।लोकतंत्र का बड़ा सवाल है किसदन में पहले दिन की उथल-पुथल इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में शीतकालीन सत्र किसी राजनीतिक परीक्षा से कम नहीं होगा। सरकार जहां विकास, अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों पर विधायी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष अधिक आक्रामक और तप्त सवालों के साथ तैयार बैठा है। इस सत्र की असली कसौटी यह होगी कि क्या संसद अपने मूल दायित्व जनता के लिए कानून बनाना और शासन पर निगरानी रखना,को पूरा कर पाएगी या फिर राजनीतिक ध्रुवीकरण इसे फिर से जाम कर देगा? लोकतंत्र का सार संवाद है, और संवाद के लिए बहस काअधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना संयम का। पहले दिन की घटनाओं ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारा राजनीतिक वर्ग इस संतुलन को पुनः स्थापित कर पाएगा। शीतकालीन सत्र की यह आरंभिक हलचल संकेत देती है कि आने वाले 18 दिन शांत नहीं रहने वाले। परंतु यदि सत्ता और विपक्ष अपने-अपने राजनीतिक हितों के ऊपर राष्ट्रहित को प्राथमिकता दें, तो यह सत्र महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दे सकता है।अंततः संसद जनता की उम्मीदों का मंच है। और इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए चाहिए न ड्रामा, न आरोपों का तूफान,बल्कि ठोस कार्य, सार्थक बहस और लोकतांत्रिक परिपक्वता। यह तभी सम्भव है,जब विपक्ष इस बात को समझे और समझकर उनकी जवाबदेही पर पुनः विचार करे।

कांतिलाल मांडोत

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:**–उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254,E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

बिजली बिल राहत योजना से सोंडासी में बड़ी राहत, उपभोक्ताओं ने 1 लाख से अधिक बकाया जमा किया

लालगंज (रायबरेली)। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी बिजली बिल राहत योजना के तहत लालगंज क्षेत्र के सोंडासी ग्राम सभा के पूरे नया गांव में बिजली विभाग द्वारा कैंप लगाया गया। कैंप में उपभोक्ताओं को भारी-भरकम छूट के साथ बकाया जमा करने का अवसर प्रदान किया गया।राज्य सरकार और यूपीपीसीएल द्वारा 1 दिसंबर से लागू की गई इस योजना का लाभ सोमवार को उपभोक्ताओं को दिया गया। कैंप के दौरान पूरे नया गांव के उपभोक्ताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हुए 1 लाख रुपये से अधिक का बकाया बिल जमा कराया।अवर अभियंता विद्युत विभाग बृजेश कुमार मौर्य ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य लंबे समय से बकाया बिजली बिल के बोझ तले दबे घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत निर्धारित शुल्क जमा करने पर उपभोक्ताओं के बकाये की गणना नई दरों पर की जाएगी और ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा।इसके बाद उपभोक्ताओं को अपना बिल एकमुश्त भुगतान या आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जाएगी, जिससे बिल चुकाने में काफी आसानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो उपभोक्ता बकाया जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।इस मौके पर एसडीओ शिवम वर्मा, एक्सियन दयाशंकर यादव, अधिशासी अभियंता राजकुमार कुर्मी, टीजी लाइन जितेंद्र सिंह, समीम, कन्हैयालाल सहित विद्युत विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

एसआईआर प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सपा ने संभाली कमान, मोहम्मद मुशीर बने लालगंज प्रभारी

लालगंज रायबरेली। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी ह्यद्वह्न प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी निचले स्तर पर अपने पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंप कर एस आई आर फॉर्म भरने से कोई भी मतदाता वंचित न रह जाए इसको लेकर हर क्षेत्र की जिम्मेदारी एक अहम सदस्य को सौंप गई वहीं समाजवादी पार्टी जनपद रायबरेली के जिला सचिव मोहम्मद मुशीर को एस आई आर लालगंज प्रभारी नियुक्त किया गया जिसको लेकर मोहम्मद मुशीर के द्वारा लगातार गांव गांव जाकर हर एक मतदाता को एस आई आर फॉर्म भरने के लिए प्रेरित के साथ फार्म भरवाए जा रहे हैं बीते सोमवार को मोहम्मद मुशीर के द्वारा खंड विकास अधिकारी लालगंज के साथ वार्ता की गई और किसी भी प्रकार की समस्या से निजात दिलाने को लेकर अधिकारियों से विचार विमर्श किया इस दौरान मोहम्मद मुशीर के द्वारा लगभग एक दर्जन गांव पहुंच कर समाजवादी कार्यकर्ताओं को मतदान प्रक्रिया को मजबूत बनाने को लेकर एस आई आर फॉर्म भरवाने तथा इस प्रक्रिया से कोई वंचित न रह जाए इसको लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया इस दौरान सरिस्ताबाद, मोहन सिंह का पुरवा,भुरकूष पुर, बहाई,जमुवावा,कानमऊ सहित अन्य गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों के फार्म भरवाए गए इस दौरान सरेनी विधानसभा अध्यक्ष जेपी यादव , सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

72 घंटे बाद भी नहीं हुई अज्ञात शव की पहचान, पुलिस ने हत्या की आशंका पर शुरू की जांच

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के धन्नीपुर गांव के पास खेत में बरामद अज्ञात शव की पहचान तीन दिन बाद भी नहीं हो सकी है। पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि ग्रामीणों की आशंका को देखते हुए हत्या के एंगल से भी जांच तेज कर दी गई है।गुरुवार सुबह उन्नाव हाईवे से सेमरपहा की ओर जाने वाली लिंक रोड के किनारे ग्रामीणों ने कीचड़ में लथपथ एक शव पड़ा देखा। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। शव पर केवल टी-शर्ट और चड्डी पाए जाने के साथ ही दोनों आंखों की पुतलियां गायब मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने प्रथम दृष्टया हत्या कर शव फेंके जाने की संभावना जताई।मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने घटनास्थल की छानबीन के बाद पंचायतनामा भरवाया और शव को मर्चरी में भिजवाया। इसके बावजूद रविवार तक मृतक की पहचान स्थापित नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि पहचान के प्रयास जारी हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

सहकारिता भवन, लखनऊ आयोजक: कन सेवा समिति कार्यक्रम

● प्रतिभा सम्मान, शिक्षा हेतु आर्थिक अनुदान, सांस्कृतिक प्रस्तुतीकरण एवं सामाजिक उत्थान समारोह।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

संवाददाता रोशनी सोनकर

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में कन सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 30 नवंबर 2025 को सहकारिता भवन, लखनऊ में भव्य 'प्रतिभा सम्मान एवं सामाजिक उत्थान समारोह' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देशभर के बोर्डों से 10वीं के 55 तथा 12वीं के 45 – कुल 100 मेधावी छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट प्रमाण-पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। समिति द्वारा समाज के 50 आर्थिक रूप से कमजोर, सिंगल-पैरेंट एवं अनाथ बच्चों को ?10,000 प्रति छात्र आर्थिक सहायता प्रदान की गई। विभिन्न जिलों से आए समाज के बच्चे-बच्चियों ने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित सांस्कृतिक लोकगीत, नाटक एवं प्रस्तुतियाँ दीं। समिति द्वारा समाज के 35 वरिष्ठ समाजसेवियों, अधिकारियों, शिक्षकों, व्यापारियों एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं को शॉल, मूमेंटो एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया गया। खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं–धर्मेंद्र सोनकर (हॉकी कोच), अरविंद सोनकर (टेनिस कोच), श्रद्धा सोनकर (फुटबॉल कोच) एवं सुधांशु सोनकर (क्रिकेट प्लेयर) को भी सम्मानित किया गया। दीप प्रज्वलन एवं प्रारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्षता कर रहे प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. आर. के. सोनकर द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। बुद्ध वंदना समाज के वरिष्ठजन श्री सिताराम सोनकर एवं चंदन सोनकर द्वारा सम्पन्न हुई। मुख्य वक्ताओं के प्रभावशाली विचार डॉ. रागिनी सोनकर (पूर्व ह्वद्धद्धह्र डॉक्टर एवं विधायक–मछलीशहर)–मुख्य वक्ता ने कहा कि 'शिक्षा शेरनी का दूध है–जो पीएगा, वही दहाड़ेगा।' उन्होंने सावित्रीबाई फुले और माता रमाबाई के संघर्षों का उदाहरण देते हुए महिलाओं एवं बच्चियों को शिक्षा के प्रति जागरूक होने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं, आवश्यकता है–सुविधाओं, अवसरों और सही मार्गदर्शन की। उन्होंने युवाओं को कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और समाज के अपलिफ़्टमेंट में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

शैलेन्द्र सोनकर (उपायुक्त–दिव्यांगजन, उ.प्र.) – मुख्य अतिथि शैलेन्द्र सोनकर ने मेधावियों को संबोधित करते हुए कहा कि 'आज का सम्मान केवल पुरस्कार नहीं, बल्कि आपके उज्वल भविष्य की पहली सीढ़ी है।' उन्होंने समाज के युवाओं से दृढ़ संकल्प, अनुशासन और उच्च लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 'शिक्षा और जागरूकता ही सामाजिक समानता और न्याय की नींव है–इसे हर घर तक पहुँचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।' डॉ. ऋ च. सोनकर (प्रमुख वैज्ञानिक - कार्यक्रम अध्यक्ष) डॉ. सोनकर ने कहा कि 'कि आधुनिक शिक्षा ही समाज को सही दिशा दे सकती है साथ ही देश को एक अच्छा नागरिक बनाने में सहयोगी होगी. छात्रों को उत्साहित करने के लिए 13 सूत्री शपथ दिलाई गई और बच्चों को अंधविश्वास पाखंड से दूर रहकर शिक्षा की

तरफ बढ़ने पर जोर दिया गया. समाज के सभी छात्रों से आवाहन किया गया कि उनके द्वारा 100% अंक प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए और तैयारी भी होनी चाहिए. टाइम मैनेजमेंट के साथ यदि छात्रों ने पढ़ाई किया तो निस्संदेह वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे. हम अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि परिवार में पढ़ने का वातावरण लगातार बनाएं रखें और बच्चों टीवी और मोबाइल के साथ सोशल साइट्स से भी यथासंभव दूरी बनाकर रखें.संविधान के पालन और समाज में जागरूक करने पर जोर दिया गया। अध्यक्ष, कन सेवा समिति– राकेश कुमार सोनकर ने कहा कि 'हमारी आज की उपलब्धियाँ हमारे महापुरुषों–विशेषकर बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर–के संघर्षों का प्रतिफल हैं। हम उनके ऋणी हैं।'

उन्होंने बच्चों से कहा कि वे केवल स्वयं आगे न बढ़ें, बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लें। उन्होंने माता-पिता और समाज के सभी प्रबुद्धजनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 'हमारा लक्ष्य है–प्रतिभा को अवसर, संघर्ष को सम्मान और समाज को दिशा देना।' मंच संचालन कार्यक्रम का संचालन समिति के प्रबंधक एडवोकेट सर्वेश सोनकर ने अत्यंत कुशल एवं गरिमापूर्ण ढंग से किया। कन सेवा समिति के पदाधिकारी संरक्षक-सिताराम सोनकर संरक्षक-भीमसेन सोनकर, रमेश पहलवान कोऑर्डिनेटर -राम नरेश सोनकर कोऑर्डिनेटर-अशोक सोनकर अध्यक्ष-राकेश कुमार सोनकर प्रबंधक एडवोकेट सर्वेश सोनकर उपाध्यक्ष शक्ति ज्योति सोनकर, प्रदीप सोनकर गैलेक्सी सचिव-डॉ. संजय सोनकर कोषाध्यक्ष-घनश्याम दास सोनकर विधि सलाहकार-एडवोकेट राजेन्द्र सोनकर उपप्रबंधक-डॉ. दयाराम सोनकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष-डॉ. श्रीतोष सोनकर समाजसेवी-जितेश सोनकर (दीपू), साजन सोनकर, रिंकू सोनकर, टिंकू सोनकर अध्यक्ष (महिला विंग)-भाग्यवती सोनकर संयुक्त सचिव-जया अटल सोनकर सदस्य निशा सोनकर, इंदिरा सोनकर, उषा सोनकर, कुमकुम सोनकर, ज्योति बाला सोनकर, हेमलता सोनकर, नमिता, सोनाली मीडिया प्रभारी-जयदीप सोनकर प्रमुख प्रचारक–अनिल सोनकर (फत्तू) सभी पदाधिकारियों ने अतिथियों को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और प्रतीक-चिह्न भेंटकर सम्मानित किया। सामूहिक भोजन कार्यक्रम के उपरांत सभी अतिथियों, प्रबुद्धजनों एवं समिति के सदस्यों ने एक साथ सामूहिक भोजन ग्रहण किया–जो सामाजिक एकता का सुंदर संदेश था।

सेंट मीरा इंटर कॉलेज का 40वाँ वार्षिक समारोह आयोजित संपन्न हुआ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के सेंट मीरा इंटर कॉलेज में 40वां वार्षिक समारोह अत्यंत भव्य और उत्साहपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की सफलता में विद्यालय प्रबंधन, विशेषकर विनोद रातड़ा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विनोद रातड़ा नहीं बताया की अलीम खान नाम की बच्ची ने टॉप किया है उसकी फीस भी माफ कर दी गई है। अलीम खान की मां को तराजू में तोला गया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण माँ सरस्वती की वंदना और दीप प्रज्वलन*: समारोह की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। एकता में ही शक्ति है। इस वर्ष का मुख्य विषय 'एकता में ही शक्ति है' रहा, जिसे छात्रों ने नृत्य, नाटकों और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। लोकनृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ असम का पारंपरिक आसामी नृत्य, गुजरात का ऊर्जा से भरपूर डांडिया, दक्षिण भारत के शास्त्रीय एवं पारंपरिक नृत्य, तथा देश के अन्य हिस्सों की लोक प्रस्तुतियाँ। योग डांस छात्रों ने योग डांस की शानदार प्रस्तुति दी, जिसने 'स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन' की प्रेरणा दी। नन्हे-मुन्नों की प्रस्तुति*: नन्हे-मुन्नों ने 'एक ज़िंदगी मेरी, 100 ख्वाहिशें' पर अपनी प्यारी और आकर्षक प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। रामायण कथा की नृत्य-नाटिका*: मंच पर प्रस्तुत की गई रामायण कथा की नृत्य-नाटिका ने दर्शकों को पौराणिक युग की यात्रा कराई। माँ-बाप की क़ीमत एक भावनात्मक नाटक– 'माँ-बाप की क़ीमत '–ने माता-पिता के प्रेम, त्याग और महत्व को बेहद संवेदनशील तरीके से दर्शाया। मातृत्व सम्मान प्रबंधन ने मातृत्व के सम्मान में एक अनोखी पहल की– 'माँ' को फलों से तौलकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण विद्यालय प्रबंधन विनोद रातड़ा ने उन छात्रों को साइकिल और ट्रॉली बैग प्रदान किए, जिन्होंने पूरे वर्ष उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए और अपनी मेहनत से विद्यालय का नाम रोशन किया। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के प्रबंधन, विनोद रातड़ा, सभी शिक्षकों और छात्रों की अथक मेहनत और समर्पण महत्वपूर्ण रहा।

उत्कृष्ट कार्य के लिए होमगार्ड राम सुफल यादव को कोतवाली प्रभारी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज/रायबरेली। कोतवाली परिसर में आज 1 दिसंबर 2025 को एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिमाह की भांति इस बार भी उत्कृष्ट सेवा देने वाले होमगार्ड को सम्मानित किया गया। समारोह का मुख्य आकर्षण रहे होमगार्ड राम सुफल यादव, जिन्हें उनकी सतर्क ड्यूटी, अनुशासित व्यवहार और लगातार मिल रही सराहनीय उपलब्धियों के लिए प्रभारी निरीक्षक जगदीश यादव व पी.सी. इंद्रमणि सिंह चौहान द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दे कि, कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने कहा कि होमगार्ड बल जिला पुलिस का अभिन्न हिस्सा है और उनकी निष्ठा व कर्तव्यपरायणता के कारण ही क्षेत्र में शांति व सुरक्षा का वातावरण कायम रहता

है। उन्होंने सभी होमगार्ड जवानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि, ऐसे सम्मान समारोह होने से उत्साह व मनोबल बढ़ता हैं। इस मौके पर होमगार्ड ए.सी.सी. बुद्धसेन शर्मा, छिटाई प्रसाद, रामदास यादव, रामयश मौर्य, रामराज यादव, लाल मोहम्मद, रमापति बाजपेई, रामकुमार सिंह, आशीष कुमार द्विवेदी, रमेश कुमार मिश्रा, तेज कुमार, शिवकरन यादव, शिवशंकर मिश्रा, रामकुमार यादव, सुरेश कुमार यादव, दिनेश सिंह, राजेश सिंह सहित आदि उपस्थित रहे।

SIR पर बवाल, विपक्ष का जोरदार हंगामा, उच्च सदन में सभापति का जोरदार स्वागत

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। इस सत्र में 19 दिनों की अवधि में कुल 15 बैठकें होंगी। विपक्षी सांसदों द्वारा बार-बार की गई नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बाद लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदर्शनकारी विपक्षी सांसदों की मुख्य माँग देश भर में मतदाता सूचियों से संबंधित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास पर चर्चा कराना था। वहीं, संसद के शीतकालीन सत्र के आरंभ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन का हार्दिक स्वागत किया। राधाकृष्णन पहली बार उच्च सदन की अध्यक्षता करने के लिए संसद पहुँचे, जिससे उनके अध्यक्ष पद पर कार्यकाल की शुरुआत हुई।

संगम फाउंडेशन द्वारा 'अवध रत्न सम्मान' समारोह का भव्य आयोजन, दानिश आजाद अंसारी और डॉ. अम्मार रिज़वी ने की शिरकत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ, 30 नवंबर: संगम फाउंडेशन के तत्वावधान में 'अवध रत्न सम्मान' का भव्य समारोह निशातगंज, लखनऊ स्थित ऑल इंडिया कैफी आजमी अकादमी में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया।

प्रोफेसर सैयद शफीक अशरफी ने सभी अतिथियों के लिए स्वागत भाषण दिया। उद्घाटन सत्र के बाद, डॉ. मोहम्मद अकमल ने संगम फाउंडेशन और अवध रत्न सम्मान की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पिछले वर्षों की उपलब्धियों और प्रमुख सेवाओं का व्यापक विवरण दिया गया। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में फाउंडेशन के निरंतर संघर्ष का उल्लेख करते हुए बताया कि यह सिलसिला 2014 से जारी है। उन्होंने जानकारी दी कि नई पीढ़ी के लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए फाउंडेशन ने एक नया पुरस्कार 'नौजवान कलमकार (युवा लेखक) अवध रत्न सम्मान' शुरू किया है। डॉ. अकमल के अनुसार, संगम फाउंडेशन ने भविष्य के लिए कई नई सामाजिक और कल्याणकारी योजनाएं तैयार की हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम जल्द सामने आएंगे।

समारोह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री (अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज) जनाब दानिश आजाद अंसारी ने संगम फाउंडेशन की सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह संस्था समुद्र से भी नायाब मोती खोजने की क्षमता रखती है और समाज में उत्कृष्ट सेवा करने वालों को सम्मानित करने में हमेशा अग्रणी रहती है। उन्होंने युवाओं को अपने बड़ों से सीखने और सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। जनाब सैयद जफर इकबाल ने अपने संबोधन में कहा कि संगम फाउंडेशन केवल सम्मान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक भावना को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा ने फाउंडेशन की सेवाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि यह संस्था सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रही है, जो इसे अन्य संस्थाओं से अलग बनाता है। प्रो. सैयद शफीक अशरफी से अपने व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे सही मायनों में 'अशरफी' हैं, जो हर मौके पर देश और समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं।

समारोह की अध्यक्षता पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉ. अम्मार रिज़वी ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने फाउंडेशन को बधाई देते हुए इसके सामाजिक, साहित्यिक और कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दो समुद्र अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक धारा में मिल जाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न विचारों वाले लोग मिलकर एक मजबूत मानवता का रूप ले लेते हैं, और संगम फाउंडेशन इन्हीं मूल्यों का सुंदर संगम है।

इन्हें मिला अवध रत्न सम्मान:

इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए निम्नलिखित विभूतियों को सम्मानित किया गया:

सैयद मंजूर अहमद अशरफी अवध सम्मान: प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर और प्रोफेसर सौबान सईद।

सैयद नईम अशरफ अवध रत्न सम्मान (पत्रकारिता): श्री आत्म प्रकाश मिश्रा और श्री प्रवीण मिश्रा।

मलिक मोहम्मद जायसी अवध रत्न सम्मान (सामाजिक एवं शैक्षिक): डॉ. नीरज शुक्ला और डॉ. एकता चौहान।

नौजवान कलमकार अवध रत्न सम्मान (साहित्य एवं शोध): डॉ. अंजू बंसल, डॉ. मोहम्मद जावेद अख्तर और डॉ. मसीह उद्दीन खान।

सभी पुरस्कार विजेताओं को शॉल ओढ़ाकर प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र (मानपत्र) भेंट किए गए।

प्रोफेसर फखर-ए-आलम आज़मी, डॉ. अब्दुल हफीज, नंदनी त्रिपाठी, डॉ. वसी अहमद आजम अंसारी, कनक दुबे, रश्मि सचान, मोहम्मद नसीम, अब्दुल्ला और मोहम्मद आदिल ने विजेताओं के सम्मान में मानपत्र प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर ने अपने प्रभावशाली अंदाज में किया, जबकि अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर सैयद शफीक अहमद अशरफी ने किया।

इस अवसर पर सैयद परवेज अशरफ, सैयद जुल्फिकार अली, सैयद अब्दुल कादिर, डॉ. जफर नकवी, डॉ. सरवत तकी, डॉ. मुनव्वर हुसैन, डॉ. मूसा रज़ा सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधार्थी, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे।

खेल में हार-जीत का महत्व नहीं प्रयास ही असली जीत : इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह

● बीएमपीएस लालगंज में दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद स्पर्धा का शुभारंभ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज,रायबरेली। कस्बे के बक्शी मेमोरियल पब्लिक स्कूल लालगंज में दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद स्पर्धा 2025 का शानदार शुभारंभ,समापन 02.12.2025 को होगा। कार्यक्रम की शुरुआत विद्या देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ मुख्य अतिथि कोतवाल प्रमोद सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर फीता काटकर स्पर्धा 2025 का शुभारंभ किया। खेल प्रांगण में बीएमपीएस खेल पताका फहराकर मैत्री और शांति का संदेश देने वाले कबूतर की जोड़ी को कोतवाल प्रमोद सिंह और प्रबंध निदेशक सुनील सिंह ने खेल प्रांगण से छोड़कर मैत्री और शांति का संदेश दिया।इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि छात्र-छात्राओं को विद्यालय स्तर से ही खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।खेल में हार-जीत का कोई मतलब नहीं।उन्होंने जीतने वाले खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के साथ-साथ हारने वाले खिलाड़ियों के भी विशेष सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि हारने वाला ही जीतने का प्रयास करता है इसलिए कभी हार से घबराना नहीं चाहिए। बालिकाओं को भी खेल के प्रति उत्साहित करते हुए कोतवाल ने उन्हें खेलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। पहले दिन नर्सरी से प्राइमरी स्तर तक के बच्चों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। छोटे बच्चों की फ्रॉग रेस,सैक रेस,लेमन स्पून रेस में छोटे बच्चों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन कर पदक हासिल किया। 50 मीटर,100 मीटर की बालक-बालिका रेस में भी जबरदस्त स्पर्धा देखने को मिली।अपनी टीम को विजय दिलाने के लिए खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रति स्पर्धा दिखाई।प्रथम,द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से पदक व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।इस अवसर पर प्रबंध निदेशक सुनील सिंह,प्रबंधक शांतनु सिंह,प्रशासनिक सचिव सिद्धार्थ सिंह,प्रधानाचार्य अभिषेक रंजन ने आए हुए मुख्य अतिथि कोतवाल प्रमोद सिंह को विद्यालय परिवार की ओर से प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में ओम शिव यादव,बीएन यादव,अनुराधा पांडे,प्रीति श्रीवास्तव, अर्चना सिंह,मृत्युंजय सिंह,श्रवण तिवारी,शिरीष तिवारी,सुधीर सिंह, विनोद चौधरी,सीमा सिंह,ममता सिंह, विभा,सुनहरा,संगीत सिंह,सरिता सिंह, आस्था सिंह,संतलाल सहित समस्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों का यथोचित योगदान रहा।अभिभावक अपने नौनिहालों के अंदर छिपी खेल प्रतिभा को देख प्रफुल्लित दिखे। इस अवसर पर अतुल त्रिपाठी,शीतला गुप्ता,योगेंद्र त्रिवेदी,अभिषेक शर्मा,अजय सिंह,शम्मी सिंह,पुत्तन सिंह सहित बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। समापन पर 02 दिसंबर को जूनियर और सीनियर वर्ग के छात्र-छात्राएं अपनी खेल प्रतिभा को दिखाएंगे।यह जानकारी बीएमपीएस के पीआरओ यशबहादुर यादव ने दी।

नाटक कलाकारों में हुई जमकर मारपीट चले लाठी- डंडे शराब पीने के बाद हुआ विवाद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में थाने से कुछ दूरी पर दो नाटक कम्पनी के कलाकारों के बीच हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। कस्बे के मुख्य मार्ग पर खुली सड़क पर लाठी-डंडों से की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद थे लेकिन किसी ने भी बीच-बचाव करने का प्रयास नहीं किया लोग तमाशबीन बने रहे और अपने मोबाइल से मारपीट का वीडियो बनाते रहे जानकारी के अनुसार, नाटक कम्पनी के कलाकार ग्राम नौआ में नौटंकी करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में कस्बे में बैठकर दोनों ने शराब पी जिसके बाद नाटक में रोल को लेकर आपसी विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते

बात इतनी बढ़ गई कि एक कलाकार ने दूसरे पर लाठियां बरसा दीं हमले में दूसरा कलाकार जमीन पर गिर गया और खुद को बचाने का प्रयास करता रहा घटना में पीड़ित की पहचान ओमप्रकाश गौतम पुत्र धनीराम निवासी नौआ महमूदपुर के रूप में हुई है जबकि दूसरे पक्ष की पहचान नसरुद्धीन पुत्र बागडूबाज के रूप में की गई है। दोनों ही नाटक कम्पनी से जुड़े हुए हैं यह विवाद अचानक मारपीट में बदल गया, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि पूरी घटना थाने के बाहर होती रही और मौके पर कोई पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिया मामले में प्रभारी निरीक्षक श्यामू कन्नौजिया ने बताया कि मारपीट का वीडियो उनके संज्ञान में आया है वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है और दोषी पाए जाने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

दिव्यांग बच्चों की तहसील स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज/रायबरेली। आज सोमवार को पाली गांव स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र में दिव्यांग बच्चों की तहसील स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें बछरावां शिवगढ़ महाराजगंज क्षेत्र के विभिन्न परिषदीय विद्यालय के दिव्यांग बच्चों ने विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग लिया। इस दौरान 100 मीटर की दौड़ में अंकित ने प्रथम स्थान हासिल किया। रंगोली में तनु ने प्रथम स्थान हासिल किया तो वहीं कुर्सी दौड़ में नेहा अव्वल रही इसके साथ-साथ चम्मच दौड़ में अंकित ने बाजी मारी। और रंग भरो प्रतियोगिता में शुभम मौर्य हस्तकला प्रतियोगिता में अंशुमन ने प्रथम स्थान पाया। इस मौके पर विशेष अध्यापक जयदेव शुक्ला अनूप मौर्य उमेश चंद्र संतोष कुमार माजीसा अनवर अनुजा शुक्ला प्रेम बहादुर मौजूद रहे।

कार्यालय ग्रा.पं. सुरजूपुर वि.ख. कटेहरी अंबेडकर नगर

निविदा सूचना

ग्राम पंचायत सुरजूपुर वि.ख. कटेहरी जनपद अंबेडकरनगर में मनरेगा/ राज्य/ 15वां/ केंद्रीय वित्त के योजनाअंतर्गत लिखित कार्य के लिए सामग्री ईट, आदि हेतु आपूर्ति ईट भट्ठा मालिकों व आपूर्तिकर्ताओं से अपने लेटर पैड पर मुहर बंद निविदाएं दिनाँक 03/12/ 2025 से 08/12/2025 तक की अवधि में ग्राम पंचायत कार्यालय के कार्य अवधि में आमंत्रित की जाती है तथा दिनाँक 08/12/2025 अधोहस्ताक्षरित निविदाओं के समक्ष सायं 4 बजे खोली जाएगी। किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा

आपूर्ति हेतु सामग्री निम्नवत है।

परियोजना का नाम- (1) खड़ंजा से अजय यादव के घर तक खड़ंजा एवं मिट्टी पटाई कार्य।

संतोष सिंह
प्रधान
ग्रा.पं. सुरजूपुर वि.ख.
कटेहरी अंबेडकर नगर

हिमांशु श्रीवास्तव
सचिव
ग्रा.पं. सुरजूपुर वि.ख.
कटेहरी अंबेडकर नगर

संक्षिप्त खबरें

पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में जल बोर्ड गुलाबी बाग का कार्यालय बना दलालों का अड्डा

पटेल नगर नई दिल्ली द्वारा बताया गया कि विधानसभा में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है जहां चुने हुए प्रतिनिधियों के कार्यकर्ता इस समय पानी की दलाली करते खूब देखे जा रहे है जिनके इशारे पर जल की सप्लाई क्षेत्र में की जा रही है। सबसे बड़े स्तर पर पानी के दलाल गुलाबी बाग पम्प पर इकठ्ठा होते हैं यही से कॉलोनी में टैंकर से पानी की सप्लाई होती है। जल बोर्ड के टैंकर ड्राइवर जिसमें बड़ी भूमिका निभाते है और जनता से पैसा लेकर इंट्री करने वालों तक पहुंचाते है जिसके बाद बिना किसी देरी जनता को पानी जल बोर्ड बेचता हैं इसमें हिस्सा जल बोर्ड के अधिकारियों का भी जरूर होता होगा क्योंकि जल बोर्ड के किसी भी अधिकारी से जनता इसकी शिकायत कर ले कोई सुनने वाला नहीं है।जनता द्वारा इसकी जानकारी समय समय पर विधायक जी को भी दी जा चुकी है लेकिन विधायक जी द्वारा कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। यह कारोबार जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों और जल बोर्ड के कर्मचारियों के मिली भगत से खूब फल फूल रहा है।पानी के लिए दर दर भटक रही जनता अंततः पानी खरीद कर पीने को मजबूर है और जल बोर्ड के कर्मचारी पानी बेचने में मशगूल है। अगर जल बोर्ड जनता को पानी नहीं दे सका तो जनता का आक्रोश कभी भी जल बोर्ड के कर्मचारियों पर फूट सकता है।

विश्व एड्स दिवस के अवसर पर नर्सिंग स्कूल के बच्चों ने निकाली जागरुकता रैली

आजमगढ़। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज नर्सिंग स्कूल आजमगढ़ के छात्र-छात्राओं द्वारा एक भव्य जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य आमजन को एचआईवी / एड्स के प्रति जागरूक करना, इसके रोकथाम, बचाव के उपाय तथा सामाजिक भ्रांतियों को दूर करना था। रैली की शुरुआत नर्सिंग संस्थान परिसर से हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय परिसर में समाप्त हुई। इस दौरान विद्यार्थियों ने स्लोगन बैनर, पोस्टर और जनजागरूकता नारों के माध्यम से लोगों को एड्स से बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण संदेश दिए, जैसे– 'एड्स से डरें नहीं, बचाव करें', 'जागरूक रहें, स्वस्थ रहें', 'जानकारी ही सुरक्षा है' आदि। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षकगण एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि एचआईवी/एड्स जागरूकता ही सबसे प्रभावी हथियार है, और इसकी रोकथाम के लिए सुरक्षित व्यवहार, समय पर परीक्षण तथा संक्रमित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान आवश्यक है। रैली में बड़ी संख्या में नर्सिंग विद्यार्थी, शिक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल रहे।

बैनामा की जमीन पर दबंग का कब्जा पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत

आजमगढ़। राहुल चौरसिया पुत्र रामकृपाल चौरसिया, ग्राम गोपालपुर, थाना-मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़,ने गाटा सं0 370 में 2 विस्वा जमीन लगभग 3 साल पहले सुधांशू सिंह पुत्र नन्दगोपाल ग्राम गोपालपुर, थाना-मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ से खरिदा था उक्त जमीन पर कब्जा व दिवाल खड़ी किया है और जमीन पर मेरा कब्जा है। विपक्षी सुधांशू सिंह पुत्र नन्दगोपाल तथा शिवसहाय, सुगन्ध सिंह ने दिनांक 24.10.2025 को मेरी बाउण्ड्रीवाल तोड़ दिया था। जिसके बावत स्थानीय थाना मेंहनगर में मु0अ0सं0-482/2025 दर्ज है। पुनः दिनांक 26.11.2025 को उपरोक्त विपक्षीगण गोलबन्द होकर हम प्रार्थी की बाउण्ड्रीवाल को पुनः ध्वस्त कर दिया। सुबह थाने पर पुनः तहरीर लिखकर दिया। दिनांक 27.11.2025 को रात्री में तीसरी बार दिवाल ध्वस्त किया गया। विपक्षीगण के चहारदीवारी को समाप्त करके अवैध कब्जा करना चाहते है। आये दिन विपक्षीगण हमे जान से मारने की व गाली गुप्ता तथा साजिश की जा रही है। थाने की मिलीभगत की वजह से स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही किया गया है। तब मजबूर होकर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से लगाई न्याय की गुहार।

केरल CM के साथ उनके मंत्री पर ED का एक्शन, 467 करोड़ के फेमा उल्लंघन मामले में कारण बताओ नोटिस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। ईडी ने मसाला बांड मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआइआइएफबी) के अधिकारियों को 466.91 करोड़ रुपये के कथित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) उल्लंघन के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीएम के अलावा ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री थामस इसाक और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव केएम अब्राहम को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। केरल की सत्तारूढ़ माकपा ने ईडी की इस कार्रवाई को ''राजनीतिक से प्रेरित'' करार दिया और दावा किया कि यह राज्य की जनता के लिए एक चुनौती है।

पार्टी ने ED की आलोचना की

पार्टी के प्रदेश सचिव एमवी गोविंदन ने ईडी की आलोचना करते हुए कहा कि नोटिस उनके ''राजनीतिक खेल'' का हिस्सा है। इसाक ने आरोप लगाया कि राज्य में चुनाव नजदीक हैं और ईडी केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए प्रचार कर रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के. मुरलीधरन ने भी आरोप लगाया कि यह केंद्र द्वारा माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ''भाजपा समर्थक'' रुख अपनाने के लिए ''मजबूर'' करने का एक प्रयास है। बहरहाल, अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि यह नोटिस 12 नवंबर को फेमा के तहत स्थापित 'नामित प्रवर्तन निदेशालय निर्णायक प्राधिकरण' द्वारा जारी किया गया था। केआइआइएफबी के अध्यक्ष के रूप में 80 वर्षीय विजयन, बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में केरल के पूर्व वित्त मंत्री इसाक और केआइआइएफबी के सीईओ के रूप में अब्राहम को नोटिस जारी किए गए हैं।

अधिकारियों ने क्या बताया?

अधिकारियों ने बताया कि यह नोटिस केआइआइएफबी और उसके अधिकारियों द्वारा फेमा प्रविधानों और आरबीआइ के मुख्य निर्देशों के कथित उल्लंघन से संबंधित है, जिसकी राशि 466.91 करोड़ रुपये है। हालांकि, राज्य सरकार ने इस मामले में किसी भी गड़बड़ी से इन्कार किया है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि केआइआइएफबी एक कार्पोरेट निकाय है जिसने 2019 में ईसीबी (बाह्य वाणिज्यिक उधार) के तहत बांड के माध्यम से 2,672.80 करोड़ रुपये जुटाने के लिए लंदन और सिंगापुर स्टाक एक्सचेंजों में 'मसाला बांड' जारी किया था।

नहर पुलिया के पास मिला व्यक्ति का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

हमीरपुर :– राठ तहसील के तुनका गांव में रविवार शाम नहर की पुलिया के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 55 वर्षीय खेमचंद पुत्र राजाराम निवासी तुनका के रूप में हुई है। घटना शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है। मृतक के बेटे चंद्रपाल ने पिता की हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक, खेमचंद मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे और शराब पीने के आदी भी थे। परिवार के अनुसार, वह पिछले आठ दिनों से घर से लापता थे। बेटे चंद्रपाल ने बताया कि पिता के गायब होने के बाद से ही उन्हें अनहोनी का अंदेशा था। रविवार शाम नहर की पुलिया के पास ग्रामीणों ने उनके पिता का शव पड़ा देखा, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर राठ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई की तथा पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इधर, परिजनों का आरोप है कि खेमचंद की हत्या कर शव नहर किनारे फेंका गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं।

कर्नलगंज की सभी रेलवे क्रॉसिंगों पर लग रहा भीषण जाम: प्रशासन मौन,जनता बेहाल

● हुजूरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण अधर में–नेताओं के वादे बने 'चुनावी जुमला'

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कर्नलगंज, गोंडा। तहसील मुख्यालय कर्नलगंज की सभी प्रमुख रेलवे क्रॉसिंगों पर रोजाना लगने वाला भीषण जाम अब आम जनता की त्रासदी बन गया है। स्कूल के बच्चों से लेकर मरीजों और कार्यालय कर्मियों तक–हर किसी को घंटों फंसे रहना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और स्थानीय प्रशासन समस्या को जानते हुए भी पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। सबसे अधिक जामग्रस्त कर्नलगंज-हुजूरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर लोगों में पिछले कई महीनों से उम्मीदें पनप रही थीं। परियोजना की स्वीकृति मिलने के बाद सेतु निगम की हलचल भी दिखी, साथ ही लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ले लिया गया। बिजली विभाग को पोल और लाइन शिफ्टिंग हेतु पत्र भी भेजा गया था। लेकिन इसके बाद से पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ना तो खुदाई शुरू हुई और ना मशीनें लगीं, न ही साइट पर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि देखी जा रही है। इससे साफ है कि विभागीय सुस्ती के चलते बहु प्रतीक्षित ओवरब्रिज का सपना अभी दूर है। लोगों का कहना है कि चुनावी मौसम में नेताओं ने यही कहकर वोट मांगे- 'अबकी बार जिता दो, फ्लाईओवर जरूर बनेगा...' लेकिन चुनाव बाद न वादा याद रहा, न जनता की समस्या। इससे नेताओं के वादे भी 'चुनावी जुमला' साबित हो रहे हैं। उधर, गोंडा-लखनऊ हाईवे के कटरा शहबाजपुर, सरयू रेलवे क्रॉसिंग, तथा कर्नलगंज-कटरा मार्ग स्थित शहीद मर्द स्थान के पास की रेलवे क्रॉसिंग पर भी हर दिन भीषण जाम लगता है। एक-एक क्रॉसिंग पर करीब 400- 500 मीटर तक वाहन फंस जाते हैं, जिससे ग्रामीण और नगर क्षेत्र के हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते ओवरब्रिज निर्माण शुरू नहीं किया गया, तो आने वाली सर्दियों और त्योहारी भीड़ में हालात और बदतर हो जाएंगे।

लोगों ने शासन और विभागीय शीर्ष अधिकारियों से हस्तक्षेप कर तुरंत निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। इस संबंध में एसडीएम कर्नलगंज से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर था।

मजदूर संघ ने खनन क्षेत्र में लगे श्रमिकों की समस्याओं का मुद्दा उठा डीएम को सौपा पत्र

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :– मजदूर संघ ने जिले में संचालित मौरम खनन क्षेत्रो में श्रमिकों के अधिकारों का हनन करने आरोप लगाते हुए सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के साथ हो रहे शोषण पर ठोस कार्यवाही करनें की मांग को लेकर जिलाधिकारी घनश्याम मीना को शिकायती पत्र सौपा है। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष शिवशरण सिंह के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में बताया कि जनपद में संचालित मौरम खंडों में लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। गाडियों को ओवरलोड भरकर जिले की प्रमुख सड़कों से निकाला जा रहा है। बताया कि खनन क्षेत्रों में श्रमिकों द्वारा बगैर किसी सेफ्टी के निरन्तर कार्य कराया जा रहा जिसमें उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनसे आठ घंटे से अधिक कार्य लिया जा रहा है तथा उन्हें किसी भी प्रकार का साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जाता है।बताया कि कार्यस्थल पर श्रमिकों ने उनसे बताया कि उनको खदान में कार्य करनें से पहले किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और न ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। उन्होंने खंड संचालकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि श्रमिकों के अधिकारों का हनन करते हुये उनको कार्य न देकर बडी बडी पोकलैंड मशीनों द्वारा खनन / लोडिंग का कार्य दिन रात में लगातार कराया जा रहा है। उन्होंने प्रकरण की उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच कराकर कार्यवाही करने की मांग की है। इस दौरान ब्रजेश कुमार बादल,दिनेश कुमार, लालाराम भारती, महेश कुमार आदि संघ के कार्यकर्तृता मौजूद रहें।

किशोरी ने फंदा लगाकर दी जान

हमीरपुर :– ललपुरा थाना क्षेत्र के पैथिया गांव में किशोरी ने फांसी लगाकर जान दी परिजनों में छाया मातम। ललपुरा थाना क्षेत्र के पौथिया गांव निवासी जगदीश ने बताया कि मैं ड्यूटी करने चला गया था पत्नी गांव में कहीं चली गई थी तभी बेटी नीशू 16 अज्ञात कारण के चलते सूना घर पाकर आंगन में लोहे की नसेनी में साड़ी से फंदा लगाकर जान दे दी। वहीं पास में एक कागज में मोबाइल नंबर लिख कर रख गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची फील्ड यूनिट टीम ने जांच की ललपुरा पुलिस ने शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललपुरा थाना प्रभारी राकेश कुमार सरोज ने बताया भौतिक सूचना के आधार पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

सामाजिक नाटक,मलूकपुर की लाल हवेली का ज्ञान कला मंच के कलाकारों द्वारा सजीव प्रस्तुति

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। 30 नवंबर 2025 को , 'ज्ञान कला मंच' के कलाकारों द्वारा राजेंद्र नगर स्थित 'स्वरांजली स्टूडियो' में सामाजिक नाटक 'मलूकपुरा की लाल हवेली 'का सफल मंचन किया गया।नाटक के कलाकारों ने अनुराग गुप्ता और श्रीमती नीता गुप्ता के निर्देशन में अपने अभिनय से सभी दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। अनुराग गुप्ता और नीता गुप्ता ने स्वयं भी नाटक में लाला पुरुषोत्तम लाल और अंगूरी देवी के किरदार निभाए।नाटक के अन्य कलाकारों राहुल मसारी, अखिलेश शर्मा,राकेश कुमार, आराध्या गरीया,प्रीति गरीया,भावना सक्सेना,अर्चना सिंह, सुमिता श्रीवास्तव और मोहित जिंदल ने भी अपनी अपनी भूमिकाओं को बखूबी निभाया। इस नाटक का लेखन भी श्रीमति नीता गुप्ता ने ही किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, द्वारका स्थित राइस फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर मधुकर वार्ष्णेय जी,उनकी धर्मपत्नी एवं 'सच्ची सहेली 'नामक ह्तह्र की संस्थापिका और समाज सेविका और द्वारका ब्लॉक, से कांग्रेस की अध्यक्षा माधुरी रावत वार्ष्णेय जी , 'स्वरांजली स्टूडियो' के संस्थापक विपिन सेठी जी,अभिनेता गायक राजकुमार भागचंदानी जी राष्ट्रपति भवन से रिटायर्ड राजपत्रित अधिकारी कविंदर जी , 'रत्नव थिएटर ग्रुप' के सीनियर अभिनेता और फाउंडर मेंबर दुर्गेश जी, 'राजेंद्र नगर आर्ट्स क्लब' के डायरेक्टर पूर्णानंद कालरा जी,थिएटर डायरेक्टर अशोक नागर जी,सुनील ढींगरा जी,और कलाकारों के बहुत से परिजन उपस्थित रहे तथा उन्होंने और अन्य दर्शकों ने सभी कलाकारों का खूब उत्साह वर्धन किया।काफी संख्या में आकर दर्शकों ने नाटक का आनंद लिया।

नाटक ने दर्शकों को शुरू से अंत तक बाँधे रखा। नाटक ' ने न केवल प्रभावित किया बल्कि कुछ सोचने पर भी विवश किया। सवा घंटे की पूरी कहानी 11 किरदारों के आस पास घूमती है ।नाटक में बताया गया कि लड़कियों का शिक्षित होना भी एक जागरूक एवं प्रगतिशील समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। अक्सर बहुत से मां बाप किसी न किसी कारण लड़कियों की शिक्षा बीच में ही छुड़ा देते हैं।नाटक के सभी कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय से न केवल दर्शकों का मन मोह लिया बल्कि हलके -फुल्के हंसी मजाक के साथ आजकल की एक गंभीर परिस्थिति की ओर भी सबका ध्यान खींचा। प्रकाश की कमान संभाली बिक्रम कुमार ने और वीडियो ग्राफी भी की।नाटक में म्यूजिक दिया विवेक यादव ने और फोटोग्राफी अंकिता गुप्ता ने।यह इस नाटक का तीसरा सफल मंचन था।

कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण जाम का वीडियो वायरल

● जाम में मरीजों के साथ फंसे लोगों ने प्रशासन पर उठाए सवाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :– कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार तड़के लगे भीषण जाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को एक महिला ने रिकॉर्ड किया, जो अपनी छोटी बच्ची के साथ घंटों से जाम में फंसी हुई थी। महिला ने प्रशासन और पुलिस की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 1 मिनट 58 सेकंड के इस वीडियो में महिला बताती है कि वह लगातार एक घंटे से यूपी-112 पर फोन कर मदद मांग रही है, लेकिन किसी तरह की सहायता नहीं मिली। उसने आरोप लगाया कि पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) के कर्मी भी जाम न खुल पाने के कारण अपनी गाड़ी में बैठे हैं और यातायात सुचारू कराने के प्रयास नजर नहीं आ रहे। महिला की नाराजगी साफ दिखती है, क्योंकि वह छोटे बच्चे के साथ भीषण जाम में फंसी है और उसे नहीं पता कि वह अपने गंतव्य तक कब पहुंचेगी। वीडियो राठ तिराहे से बेतवा नदी पुल के बीच का बताया जा रहा है, जहां रविवार तड़के वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस दौरान यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई बसों में बैठे लोगों को मजबूरी में पैदल चलना पड़ा, जबकि कई बारातें भी समय पर नहीं पहुंच सकीं। शादी-ब्याह के सीजन में इस मार्ग पर जाम की समस्या और गंभीर हो जाती है। भारी ट्रैफिक, ट्रकों की धीमी आवाजाही और सड़क किनारे लगी दुकानों के कारण यातायात अक्सर बाधित रहता है। जाम की वजह से स्कूली बच्चे, दैनिक यात्री और एंबुलेंस में मौजूद मरीजों तक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वायरल वीडियो में एक एंबुलेंस को भी जाम में फंसा देखा गया, जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि शादी के मौसम में विशेष रूप से इस मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए और अवैध पार्किंग एवं अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की

श्रीमद्भागवत कथा में श्रीकृष्ण-बलराम की बाल लीलाओं का मनोहर वर्णन, पंडाल भक्तिमय हुआ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :– सुमेरपुर कस्बा में श्री गायत्री महायज्ञ की 68वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के छठवें दिन कथा व्यास द्वारा भगवान श्रीकृष्ण और बलराम की मनोहर बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया। कथा स्थल पर सुबह से ही भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई थी, जिससे पंडाल समय से पहले ही श्रद्धालुओं से भर गया। कथा व्यास दुर्गा प्रसाद द्विवेदी ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार देवकी-वासुदेव के घर जन्म लेने के बाद नंदगाँव में पहुंचकर बालकृष्ण ने यशोदा मैया और नंद बाबा के आँगन को अपना माधुर्य प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने श्रीकृष्ण और बलराम के नामकरण संस्कार का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान के अनेकों नाम हैं, किंतु 'श्रीकृष्ण' नाम यशोदा मैया द्वारा रखा गया होने के कारण सबसे अधिक प्रिय और प्रचलित है। कथा व्यास ने आगे श्रीकृष्ण की विविध बाल लीलाओं–माखन चोरी, ग्वाल बालों के साथ उनकी चंचल हरकतें और पूतना वध जैसे प्रसंगों का विस्तार से उल्लेख किया। इन प्रसंगों को सुनकर उपस्थित श्रद्धालु भक्ति और भावनाओं से परिपूर्ण हो गए। कथा के दौरान बार-बार 'राधे-राधे' और 'जय श्रीकृष्ण' के जयघोष गूंजते रहे, जिससे वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक और अलौकिक हो उठा। कथा सुनने के लिए महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की बड़ी संख्या मौजूद रही। कई भक्त परिवार सहित पहुंचे और कथा पंडाल के बाहर लगे भंडारे और प्रसाद वितरण में भी शामिल हुए। इसी अवसर पर लगे मेले में भी कस्बे के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। झूले, खिलौनों की दुकानें, खाद्य स्टॉल और अलग-अलग आकर्षणों ने मेले को उत्सव जैसा माहौल प्रदान किया। बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

18 वीं बिहार विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दिया- प्रमोद कुमार पटेल

गोपालगंज: गोपालगंज बिहार प्रदेश जनता दल युनाइटेड के प्रदेश महासचिव सह पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने नव गठित 18 वीं बिहार विधानसभा के नव निर्वाचित सभी सदस्यों को आज विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव द्वारा विधानसभा सदस्य के रूप मे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मङ्गल पांडेय, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार, अमरेंद्र कुमार पांडेय, मंजीत कुमार सिंह, मिथिलेश तिवारी, रामसेवक सिंह, सुबास सिंह, इंद्रदेव सिंह, हेमनारायण साह, भीष्म प्रताप सिंह, सहित सभी 243 विधायको को शपथ ग्रहण करने पर बधाई एवं उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं दिया है श्री पटेल ने कहा कि मुख्य मंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पांच साल का सफल कार्यकाल पुरा होगा और विकास, रोजगार, नौकरी, उधोग के क्षेत्र में बिहार की प्रगति होगी।

आठवें वेतन आयोग में पेंशनरों के कल्याण एवं पेंशन संशोधन को शामिल करने की उठाई मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :– पेंशनर्स संघ ने 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सन्दर्भ शर्तों में पेंशनरों के कल्याण एवं पेंशन संशोधन को शामिल करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से सम्बोधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को सौपा है। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान के संरक्षक भगवान दास द्विवेदी की अगुवाई में दिए ज्ञापन में बताया कि 8 वें केन्द्रीय बेतन आयोग के गठन के पश्चात् देश भर के करोंडो सेवानिवृत्त पेंशनरों में आशा का वातावरण बना था कि आयोग में कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों के हितों की भी समान रूप से समीक्षा की जायेगी। बेतन आयोग के प्रारम्भिक उद्देश्य में कहा गया था कि यह प्राविधान उन लाखों पेंशनरों के लिये न्याय और समानता का आधार था जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्रसेवा में समर्पित किया है। इससे यह विश्वास मिला था कि उनकी आर्थिक सुरक्षा और भलाई बेतन आयोग की मुख्य भावना का हिस्सा रहेगी। किन्तु जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में पेंशनरों से सम्बन्धित यह महत्वपूर्ण बिन्दु पूरी तरह से हटा दिया गया। केन्द्रीय पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के बैध अधिकारों को अनदेखा कर दिया गया है। यह उन पेंशनरों के साथ हुये अन्याय का भी द्योतक है जिन्होंने अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष राष्ट्र की सेवा में लगाया है। उन्होंने पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण, मंहगाई राहत तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभो को भी 8वें बेतन आयोग की सन्दर्भ शर्तों में शामिल करने की मांग की है।

नेबुआ स्थित विद्यालय में मिशन शक्ति कार्यक्रम खानापूर्ति

सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के नेबुआ स्थित एक विद्यालय में सोमवार को मिशन शक्ति के तहत आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम महज़ औपचारिकता साबित हुआ। डुमरियागंज थाने की महिला उपनिरीक्षक की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत तो हुई, लेकिन छात्राओं को न तो योजनाओं की जानकारी दी गई और न ही किसी प्रकार की जागरूकता पर चर्चा कराई गई। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में मिशन शक्ति की रूपरेखा का सिर्फ औपचारिक परिचय दिया गया।सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, स्वावलंबन और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देना है, लेकिन विद्यालय में आयोजित यह कार्यक्रम अपने मूल लक्ष्य से काफी दूर रहा।

भारतीय सिन्धु सभा की संगठनात्मक बैठक संपन्न

चित्रकूट: भारतीय सिन्धु सभा द्वारा सोमवार को संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें बांदा और चित्रकूट जिलों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिसमें संगठन को सक्रिय करने और आगामी आयोजनों पर चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं से आगामी 27 और 28 दिसंबर को कानपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने का आग्रह किया गया। बैठक में संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ बनाने, कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने तथा भविष्य की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। इस मौके पर बैठक में जिलाध्यक्ष राजीव लगानी, अशोक अगनानी, साईं अमरलाल, प्रेमचंद आहूजा, नरेश कुमार, मोतीराम लालवानी, राजीव लखमानी, भास्कर आसवानी, मुनिराज ज्ञानचंदानी, दीपक अंशवानी, गिरधारी चंदानी, गोविंद खत्री समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ऑनलाइन उपस्थिति और गैर-विभागीय कार्यों के विरोध में सचिवों का चरणबद्ध आंदोलन शुरू

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :– सुमेरपुर ब्लॉक कार्यालय में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति ने ऑनलाइन उपस्थिति (एफआरएस) प्रणाली और गैर-विभागीय कार्यों के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार से समिति के सदस्य केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। यह चरण 1 से 4 दिसंबर तक चलेगा, जिसके माध्यम से सचिव सरकार तक अपनी समस्याओं और मांगों को मजबूती से पहुंचाना चाहते हैं। समिति के जिलाध्यक्ष और महामंत्री ने बताया कि एफआरएस लागू होने के बाद सचिवों पर कार्य का दबाव काफी बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क और तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना बड़ी चुनौती बन गया है। इसके अतिरिक्त, गैर-विभागीय कार्यों का बोझ भी नियमित जिम्मेदारियों के साथ तालमेल बैठाने में बाधा पैदा कर रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर सचिव लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार से समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। ठुविरोध के अगले चरण के तहत 5 दिसंबर को सभी सचिव ब्लॉक मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद समिति के सभी सदस्य जनपद के सरकारी व्हाट्सएप ग्रुपों से लेफ्ट हो जाएंगे, ताकि दूर-दूर रहकर दिए जाने वाले अनावश्यक निर्देशों से बचा जा सके। समिति ने आगामी कार्यक्रम भी घोषित कर दिए हैं। 10 दिसंबर से सभी सचिव अपने निजी वाहनों का उपयोग पूरी तरह बंद कर देंगे। वहीं 15 दिसंबर को सचिव अपने-अपने विकास खंडों में आवंटित डोंगल जमा कर देंगे, जिससे तकनीकी निर्भरता खत्म करने का

संदेश दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में अमित तिवारी, उमेश कुमार, आदित्य कुमार, शिवशंकर पाल, सुरेंद्र पटेल, सोनाली सचान, संजय सिंह, आशीष कुमार, मनीष कौशिक, महेंद्र प्रताप और मनोज गुप्ता सहित अनेक सचिव मौजूद रहे।